04 - बेलगाम नक्सलियों पर कसता शिकंजा

05 - असमानता, बेरोजगारी, रोजगार एवं कौशल गुणवत्ता की समस्या

A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 20 अप्रैल, 2024

06- सड़क बनी सब्जी बाजार, लोगों का चलना हुआ दुश्वार

07- भाजपा के शासन में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, मुख्यमंत्री ने...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 21 अंक 223 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या मान लें कि संविधान न तो खतरे में है और न ही असुरक्षित?

प्रेम कुमार

संविधान को खतरे में बताए जाने के बीच यह बात बड़े जोर-शोर से उठाई जा रही है कि भारत का संविधान बदला ही नहीं जा सकता। बीते एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार यह बात कही है कि 'मोदी तो क्या बाबा साहेब अंबेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते।'

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कमोबेश ऐसा ही कह रहे हैं- 'मोदी में दम नहीं कि वे संविधान बदल सकें'। लालू प्रसाद तो यहां तक कह रहे हैं कि जो कोई भी संविधान बदलने की कोशिश करेगा जनता उसकी आंखें निकाल लेगी। तो, क्या मान लिया जाए कि संविधान न तो ख़तरे में है और न ही असुरक्षित? संविधान में अब तक 127 संशोधन हो चुके हैं। इन संशोधनों को संविधान बदलना नहीं कह सकते। फिर, संविधान बदला कैसे जाएगा?

संशोधनों के माध्यम से ही तो संविधान में बदलाव होगा। इसका मतलब यह है कि संविधान संशोधन को जरूर संविधान बदलना नहीं कह सकते लेकिन संविधान बदलने का रास्ता भी संविधान संशोधन ही है।

समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखण्डता से जुड़कर हमारा संविधान मजबूत हुआ है। 42वें संविधान संशोधन जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखण्डता जैसे शब्द जोड़े गये। बीजेपी इन दिनों इसे संविधान बदलना ही कहती रही है। बीजेपी के नेता अक्सर इन शब्दों को संविधान से हटाने की जरूरत बताते रहे हैं।

इसके उलट सच यह है कि स्वयं बीजेपी ने अपने संविधान में 'गांधीवादी समाजवाद' को जोड़ा था और वास्तव में 46वें संविधान संशोधन पर अपनी सहमति दी थी। मगर, आज की बीजेपी बदल गयी है। बीजेपी-आरएसएस का इरादा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसी सोच से छुटकारा पाना है। वो इसके समांतर हिन्दुत्व, रामराज्य, हिन्दू राष्ट्र जैसे शब्द संविधान में रखना चाहते हैं।

इस मंशा का ऐलान बीजेपी और संघ के नेता समय-समय पर करते रहे हैं। लेकिन, इन दिनों जो बहस संविधान पर खतरे को लेकर चली है उसके पीछे दो स्पष्ट कारण हैं- एक कारण है बीजेपी सरकार की विपक्ष के प्रति असहिष्णुता की नीति और दूसरा कारण है स्वयं बीजेपी की ओर से संविधान में बदलाव की ललक जिसे वे छिपा नहीं पाती।

अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, प्रेम कुमार, लल्लू सिंह, अरुण गोविल जैसे नेताओं ने लगातार अपने बयान से संविधान बदलने की इच्छा का खुलकर इजहार किया है। बीजेपी ने कभी इन बयानों का खंडन नहीं किया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इन नेताओं पर नकेल कसने की जरूरत नहीं समझी।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए कि बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाते तो संविधान नहीं बदल पाते? क्या वे कहना चाहते हैं कि अब संविधान बदलने की ताकत केवल और केवल बीजेपी में आ गयी है? ऐसा करने की क्षमता बीजेपी के अलावा अब किसी और में नहीं रही?

बीजेपी को क्यों चाहिए 400+ सीटें?- आखिर बीजेपी को 400 पार सीटें क्यों चाहिए? सरकार बनाने के लिए इतने बड़े बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता इस बहुमत को एक जरूरत के तौर पर बता रहे हैं। यह जरूरत संविधान बदलने की है। ऐसा संविधान में बड़े संशोधनों के जरिए किया जाएगा।

ये संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत लाकर ही संभव है। राज्यसभा में अब भी बीजेपी के पास सामान्य बहुमत नहीं है। ऐसे में संयुक्त सेशन बुलाए जाने की स्थिति में राज्यसभा में घटी हुई ताकत की भरपाई भी लोकसभा सदस्य के तौर पर हो।

यही कारण है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 400 पार का नारा उसके लिए बड़ी शक्ति रहने वाली है। इस संभावित शक्ति की मंशा पर ही सवाल है कि क्या इस शक्ति का दुरुपयोग जनता के ही खिलाफ तो नहीं होगा?

विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के मन में लोकतंत्र के लिए आदर नहीं है। वह हर हाल में सत्ता में बने रहने के लिए वांछित परिवर्तन करने में लगी हुई है। सत्ता में रहते हुए 147 सांसदों का निलंबन और इस दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना यह बताता है कि बीजेपी संसदीय लोकतंत्र को कितना तवज्जो देती है।

चुनाव के समय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना भी संसदीय लोकतंत्र और चुनाव में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

सत्ता की ताकत का दुरुपयोग- केंद्रीय एजेंसियों का पक्षपातपूर्ण तरीके से विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल अब साबित करने की बात नहीं रही। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ता प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल लोकतंत्र को कुचलने के लिए किया गया, अब इसमें कोई संदेह बाकी नहीं रह गया है।

विपक्ष को लगता है कि एक बार फिर अगर बीजेपी को मौका मिला तो वो सबसे पहले उन ताकतों को नष्ट करेंगे जिन्होंने लोकतंत्र की आवाज को बुलंद रखा है। विपक्ष जिस जोर से लोकतंत्र बचाने की आवाज़ उठा रहा है उससे अधिक जोर लगाकर बीजेपी ऐसा करती दिख रही है।

जनता के सामने यही चुनौती है कि सही मायने में लोकतंत्र के रक्षक कौन हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लोकतंत्र की आवाज उठाने का दावा करने वालों को परखना होगा। लोकतंत्र का किसने अतीत में कितना सम्मान किया है इसकी भी परख जरूरी है। ऐसा करके ही जनता सही मायने में लोकतंत्र के रखवाले की पहचान कर सकेगी। आम चुनाव अवश्य संविधान बचाने की चिंता से लैस इस देश को अपनी राय बनाने में मदद करेगी।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

प्रथम चरण

त्रिपुरा-बंगाल में बंपर वोटिंग, बिहार में 'सुस्ती'

● देश के 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म ● मध्यप्रदेश में 65, राजस्थान में 50 फीसदी मतदान ● बंगाल में 77 फीसदी वोट डाले गए,मणिपुर में हिंसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक, शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में 77.57 प्रतिशत हुई। सबसे कम वोटिंग बिहार में 46.32 प्रतिशत हुआ। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 62.8 प्रतिशत है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूचबिहार में हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल हैं। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों (मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर) पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थीं। अन्य को 23 सीटें मिली थीं। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। फर्स्ट फेज में 1,625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1,491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद

26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वेस्ट यूपी की आठ सीटों पर खूब वोट पड़ रहे हैं। वोटिंग में हर वर्ग में जज्बा दिख रहा है। बुजुर्ग, युवा, विकलांग, दुल्हन हर कोई बूथ पर पहुंचा। हालांकि, वोटिंग के दौरान कई जिलों में जगह-जगह ईवीएम खूब हाफी। वोटर लिस्ट से नाम गायब करने और वोट नहीं डालने देने, बूथ कैप्चरिंग के आरोप का दौर चला। इनकी चुनाव आयोग से शिकायत की गई। समस्याओं को लेकर कई जगह चुनाव बहिष्कार भी किया गया। कहीं वोटर मान गए तो कहीं जिद पर अड़े रहे। इन सीटों पर सांसद कौन बनेगा, इसका खुलासा चार जून होगा। वैसे सभी सीटों पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है और वोटरों में बंटवारे का असर भी दिख रहा है। वेस्ट यूपी के 9 जिलों की 8 लोकसभा सीट सहारनपुर, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में शुक्रवार को सुबह 7 से मतदान जारी है।

एमपी में छह सीटों पर बंपर वोटिंग, छिंदवाड़ा में विवाद

छिंदवाड़ा में भाजपा-कांग्रेस समर्थकों के बीच चली कुर्सियां

भोपाल। मध्य प्रदेश की छह सीटों पर शाम पांच बजे तक 63 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हो चुका है। शाम पांच बजे तक प्रदेश में 63.25 प्रतिशत मतदान हुआ। छिंदवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा 73.85 फीसदी तो सीधी में सबसे कम 51.24 प्रतिशत वोट पड़े। अनूपपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 205 सिवनी जैतहरी में 22 वर्ष के दिव्यांग युवा मतदाता उमेश कुमार राठौर पिता जयलाल ने मतदान केंद्र पहुंचते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दिव्यांग उमेश राठौर चल फिर पाने में सक्षम नहीं है और अपने परिवार के लोगों के साथ वह मतदान केंद्र तक पहुंचे जहां मतदान केंद्र में व्हीलचेयर से मतदान करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान दिव्यांग युवा मतदाता के मतदान के प्रति उत्साह को देखकर जैतहरी थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र कोल द्वारा उनका उत्साह वर्धन किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्यप्रदेश की 6 सीटों- छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर वोटिंग हुई।

जबलपुर के पनागर में मतदान का बहिष्कार

जबलपुर में पनागर विधानसभा के धरहर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। शाम 5 बजे तक यहां सिर्फ 13 लोगों ने वोट डाले जबकि कुल वोटर्स की संख्या 800 है। वोट करने वालों में शासकीय कर्मचारी और सरपंच-पंच शामिल हैं। इनके अलावा किसी भी ग्रामीण ने वोट नहीं डाला। एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर का कहना है कि गांव में सड़क नहीं होने का मुद्दा उठाकर बहिष्कार किया जा रहा है।

ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर इजराइल का हमला

तेलअवीव (एजेंसी)। इजराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे (भारतीय समयानुसार) जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ है। इसके अलावा इराक और सरिया में भी एयरस्ट्राइक की गई हैं। इस्फहान वही प्रांत है, जहां नतान्ज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी। हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के जन्मदिन के दिन हुआ है। हालांकि, इजराइल ने अब तक हमले की पुष्टि नहीं की है। वहीं, ईरान ने कहा है कि उन्होंने इस्फहान में 3 ड्रोन्स को मार गिराया है।

इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं

पीएम मोदी बोले-आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा- हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर में दमोह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन को डेंगू-मलेरिया कहते हैं। भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा- परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वे कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है, न कभी डर सकता है। पीएम मोदी ने कहा- जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो। घटनाएं घट रही हो। तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। ये काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, ये हमने बीते वर्षों में देखा है। पीएम मोदी ने कहा- जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण दिया है। भाजपा ने घोषणा पत्र में घोषणा की है कि मुद्रा योजना में मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए तक किया जाएगा। कोविड का इतना बड़ा संकट आया। मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत ले आई। करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो न किसी से दबती है, न किसी के सामने झुकती है। मोदी बोले- ओरछा में हमारे भगवान राम राजा के रूप में विराजित हैं। बुंदेलखंड की धरती देख रही कैसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं, हमारा सनातन डेंगू-मलेरिया है। अध्योध्या में राम मंदिर बना है, उसके भी ये विरोधी हैं। राम की पूजा को पाखंड बताते हैं।

'बाबा' की याचिका, बिहार-छत्तीसगढ़ में ऐक्शन न हो

● अदालत ने कहा-शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर दर्ज कई FIR क्लब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश समेत 2 जजों की बेंच ने बाबा रामदेव से उन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख जुलाई में तय की है। बाबा रामदेव के खिलाफ IMA के पटना (बिहार) और रायपुर (छत्तीसगढ़)

चैप्टर ने 2021 में FIR की थी। अपनी याचिका में रामदेव ने केंद्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और IMA को पार्टी बनाया है। रामदेव ने इन FIR पर एक्शन रोकने की मांग भी की थी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ IMA की याचिका पर पहले से सुनवाई जारी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन की बेंच ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को है। इसी बीच, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी मामले में पार्टी बनने की परमिशन मांगी है। DMA ने आरोप लगाया गया है कि रामदेव ने एलोपैथी का अपमान किया और लोगों को प्रैक्टिकल और प्रोटोकॉल की अवहेलना करने के लिए उकसाया। DMA, जिसमें 15,000 डॉक्टर सदस्य हैं, ने दावा किया है कि रामदेव की पतंजलि ने कोरोनिल किट बेचकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। इसे किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने सर्टिफाई नहीं किया गया था।

सुप्रभात

गली-कूचे में सन्नाटा बहुत है
किसी ने रात को डाटा बहुत है।

मुहब्बत कर तो लें हम दुश्मनों से
मुहब्बत में मगर घाटा बहुत है।

रसोई में किसी की झांकना मत
पनीला आजकल आटा बहुत है।

जरा कुछ देर बैठो,पास मेरे
अकेले वक्त को काटा बहुत है।

पुरानी खाइयां गहरी थीं मन में
यक़ीनन वक्त ने पाटा बहुत है।

मगजमारी से आजिज आ चुका हूं
सियासत ने मगज चाटा बहुत है।

बसेरा खूब करते हैं पखेरू
ये बरगद देखिए नाटा बहुत है।

सफर कोई भी हो, है जानलेवा
सभी के पास फर्राटा बहुत है।

- राकेश अचल

भोपाल का तापमान

अधिकतम 40 °c | न्यूनतम 29°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 20 अप्रैल 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

कश्मीर में हथियार पहुंचाने के लिए लश्कर ने बदला पैटर्न

खालिस्तानी पंजाब के रास्ते हथियार पहुंचा रहे, पहले पाकिस्तान से मंगाए जाते थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में अपने आतंकियों तक घातक हथियारों और विस्फोटक पहुंचाने के अपने पैटर्न में बदलाव किया है। पहले जहां पाकिस्तान से सीधे कश्मीर हथियार व विस्फोटक पहुंच रहे थे, वहीं अब यह हथियार पाकिस्तान से वाया पंजाब होकर कश्मीर में लश्कर के आतंकियों तक पहुंच रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर के आतंकियों तक हथियारों की आपूर्ति का काम बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े खालिस्तानी आतंकी द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। खालिस्तानी आतंकी द्वारा

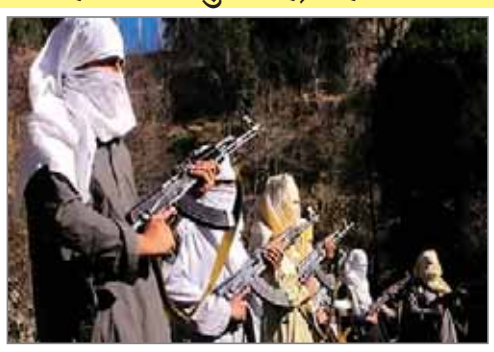

देश में अन्य आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल नेटवर्क तक पहुंचाने के बारे में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है। खुफिया जांच एजेंसियों ने सुरक्षा जांच एजेंसियों को लश्कर कमांडर जुनैद के कश्मीर आने व स्लीपर सेल ऐक्टिव कर कुलगाम में गुप्त बैठक करने की सूचना दी थी। बब्बर खालसा का वांटेड खालिस्तानी आतंकी रमनदीप सिंह उर्फ रमन पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है। रमनदीप सिंह उर्फ रमन को एनआईए ने भगोड़ा घोषित किया हुआ है और वह एक वांटेड आतंकी है।

केरल में बर्ड फ्लू फैला, 21 हजार पक्षी मारेगा प्रशासन

8 दिन में 3500 पक्षी मरे, जिला प्रशासन का दावा-इंसानों में फैलने की संभावना नहीं

अलप्पुझा (एजेंसी)। केरल के अलप्पुझा जिले में दो जगह जानलेवा बर्ड फ्लू के फैलने की खबर हड़कंप मच गया है। यहां एडथवा ग्राम पंचायत के वार्ड एक और चेरूथाना ग्राम पंचायत के वार्ड 3 में बत्तखों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। एडथवा मे 12 अप्रैल से अब तक 3 हजार तो चेरूथाना में 250 पक्षी मारे चुके हैं। मरे हुए पक्षियों के सैंपल जब भोपाल स्थित लैब भेजे गए, तब इनमें एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अब यहां 21 हजार पक्षियों को मारा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडथुआ में अब्राहम ओसेफ की 7500 बत्तखों, और चेरुथाना में रघुनाथन चिरयिल की 2000 और देवराजन टीकी 15000 बत्तखों में हफ्ते भर पहले से वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे थे। रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर एलेक्स वर्गीस ने 25 अप्रैल तक बत्तख, चिकन, बटेर और अन्य घरेलू पक्षियों के मांस, अंडे और अपशिष्ट (खाद) की आवाजाही, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

संक्षिप्त समाचार

भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना शुक्रवार को फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला बैच सौंप दिया है। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 2,966 करोड़ रुपए की डील की थी। इंडियन एयरफोर्स ने एम-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपीन मरीन कॉर्प्स को सौंपा गया है। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किमी है। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के

मुताबिक फिलीपींस इन मिसाइलों को साउथ चाइना सी पर तैनात करेगा। भारत ब्रह्मोस सुपरसॉनिक मिसाइल के तीन सिस्टम फिलीपींस को सौंप रहा है। हर एक सिस्टम में दो मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके जरिए सबमरीन, शिप, एयरक्राफ्ट से दो ब्रह्मोस मिसाइलें 10 सेकेंड के अंदर दुश्मन पर दागी जा सकती है। इसके अलावा भारत फिलीपींस को मिसाइल ऑपरेट करने की भी ट्रेनिंग देगा।

दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए चीफ नियुक्त

- अभी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ हैं, 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार

नई दिल्ली (एजेंसी)। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात इसकी घोषणा की। दिनेश त्रिपाठी वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जगह लेंगे। वे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी इसी दिन पदभार संभालेंगे। दिनेश त्रिपाठी अभी नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ हैं। वे इससे पहले

पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफीसर कमांडिंग-इन-चीफ रह चुके हैं। अपने 39 साल लंबे करियर में उन्होंने भारतीय नौसेना के कई अहम असाइनमेंट्स पर काम किया है। वाइस एडमिरल दिनेश 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशंड हुए थे। वे कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्पेशलिस्ट हैं। वे नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफीसर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफीसर रहे हैं। उन्होंने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मुंबई के एग्जीक्यूटिव ऑफीसर और प्रिंसिपल वारफेयर ऑफीसर के रूप में भी काम किया है। दिनेश त्रिपाठी ने किर्च, त्रिशूल और विनाश जैसे नौसैनिक जहाजों की कमान भी संभाली है। दिनेश त्रिपाठी ने कई अहम ऑपरेशनल और स्टाफ नियुक्तियों पर भी काम किया है। इसमें मुंबई में फ्लीट ऑपरेशन्स शामिल है।

अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन

कहा-इस बार का चुनाव बेहद अहम, मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं

गांधीनगर (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। यहां 7 मई को वोटिंग होनी है। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधीनगर की जनता का मुझे हमेशा से सहयोग मिला है। क्षेत्र में विकास के सभी काम हुए हैं। इस बार का चुनाव बेहद अहम है। मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने गांधीनगर सीट से अपना नॉमिनेशन भरा है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि जिस सीट से लालकृष्ण अडवानी, अटलजी ने प्रतिनिधित्व किया है और खुद नरेंद्र मोदी जी यहां से

मतदाता हैं। उस सीट से प्रतिनिधत्व करने का मौका मिला है। 30 साल से मैं गांधीनगर से विधायक और सांसद बना, जनता के लिए ढेरों काम किए। यहां के लोग मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते हैं। मैं एक छोटे से बूथ कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कल कुछ सीटों पर बीजेपी-कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था।

चारधाम यात्रा में पहली बार ले जा सकेंगे चार्टर्ड हेलीकॉप्टर, बना प्लान

किराया 1.95 लाख; 4 दिन में 14 लाख रजिस्ट्रेशन, टूटेगा पिछला रिकॉर्ड

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा का उत्साह इस बार काफी ज्यादा है। बीते 4 दिन में 14 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछली बार चार महीने में 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार यह रिकॉर्ड टूट सकता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीएमडी सी. रविशंकर के मुताबिक पहली बार चारधाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। इसमें 4 लोग एक धाम की यात्रा साढ़े तीन लाख रु. में कर सकते हैं। यदि चारों धाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर लेते हैं तो प्रति व्यक्ति 1.95 लाख देने होंगे। किराए में आना-जाना, रुकना, खाना शामिल है। हेलीकॉप्टर भी वहीं रहेगा। एक ही दिन में वापसी का रेट 1.05 लाख रु. रहेगा। सामान्य हेलीकॉप्टर सेवा का किराया 5 फीसदी बढ़ा है। गौरीकुंड से 18 किमी

पहले फाटा से केदारनाथ जाते हैं तो एक तरफ का प्रति व्यक्ति किराया 2,886 रु. होगा। पिछली बार ये 2,749 रु. था। गुप्तकाशी से 4,063 रु. रहेगा, जो 3,870 रु. था। पहले हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग 15 दिन के स्लॉट में होती थी। इस बार एक माह का स्लॉट रहेगा। 10 मई से 20 जून और 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक और बुकिंग की हेलीयात्रा वेबसाइट से 20 अप्रैल से होगी।

2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही

इनका रिजेक्शन पहले हो चुका

यूपी के अमरोहा में पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश के गठबंधन पर उठाए सवाल

अमरोहा (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। मंच पर ढोलक देकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से क्रिकेटर मो. शमी का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने फ्लॉप फिल्म के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा- यूपी में फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। जिसका पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। प्रधानमंत्री बोले-तुष्टिकरण के खेल ने यूपी को और खासकर हमारे पश्चिमी यूपी को दंगो की आग में जलाया था। यहां के लोग गुंडाराज का वो दौर कभी भी भूल नहीं सकते। आए दिन दंगे होते थे। लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग गए थे। पीएम मोदी ने कहा- इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। अभी मैं द्वारका गया और समुद्र में नीचे जाकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की आस्था और भक्ति को ये लोग सिर्फ वोटबैंक के लिए खारिज कर रहे हैं। पीएम मोदी बोले- सीएम योगी ने गन्ना किसानों की चिंता की। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीद के साथ ही रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है।

सावधान! इस बार गर्मी और ज्यादा ढाएगी कहर

125 जिलों में सूखे जैसी स्थिति मौसम विभाग ने चेताया

नई दिल्ली (एजेंसी)। गर्मी का सितम जारी है। लू का प्रकोप भी शुरू हो चुका है। देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों सूखे जैसी स्थित का सामना कर रहे हैं। भारत मौसम विभाग विभाग ने 14 मार्च से 10 अप्रैल के बीच के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक, देश भर के करीब 125 जिले सूखे जैसे हालात से जूझ रहे हैं। साल 2023 की तुलना में देखें तो इस वक्त 33 जिले ही ऐसी स्थिति का सामना कर रहे थे जिसमें अबकी बार 279 फीसदी की बढ़ोतरी है। मार्च के शुरुआती दिनों की तुलना में इसमें 27 फीसदी का उछाल आया है। जिन 125 जिलों का ऐसा हाल है वे 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इसलिए इस बार गर्मी के शुरुआती दिनों में ही सूखे की समस्या काफी व्यापक नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और तमिलनाडु सबसे ज्यादा सूखे की चपेट में दिख रहे हैं। इन राज्यों के कई जिले ड्राई से लेकर एक्सट्रीम

ड्राई कंडीशन का सामना कर रहे हैं। सीनियर आईएमडी साइंटिस्ट राजीव चट्टोपाध्याय ने बताया, इन जिलों को ड्राइ कैटेगरी में रखा गया है जिनका वैल्यू -1 से कम है। मालूम हो कि इसके जरिए पानी की मांग पर बढ़ते तापमान का असर मापा जाता है। जिन इलाकों का वैल्यू -1 से नीचे है वहां कम बारिश की वजह से सूखे की स्थिति बन सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा जैसे इलाकों के लिए अच्छी खबर है। यहां शनिवार, रविवार और सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने का अनुमान है।

कर्नाटक के कॉलेज में कांग्रेस नेता निरंजन की बेटी की हत्या

पूर्व क्लासमेट ने चाकू से शरीर पर 7 वार किए, प्रपोजल ठुकराने से नाराज था

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के हुबली स्थित बीवीबी कॉलेज कैंपस में गुरुवार को कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की 23 साल की बेटी नेहा हिरेमथ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नेहा एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसी कॉलेज के एक ड्रॉपआउट स्टूडेंट फैयाज खोंडुनाईक (23) ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए। हमले में फैयाज को भी चोटें आईं। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां नेहा को मृत घोषित कर दिया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें फैयाज नेहा पर हमला करता हुआ दिखा। पुलिस ने बताया कि नेहा और फैयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण फैयाज ने घटना को अंजाम दिया। हुब्बली-धारवाड़ की पुलिस कमिश्नर रेणुका एस सुकेमार ने कहा कि इस मामले में कल एफआईआर दर्ज की गई

थी, जिसके एक घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमने सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, घटना शाम 5 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि नेहा कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही थी। इसी दौरान फैयाज उसके सामने आ गया। दोनों के बीच पहले कुछ बातचीत हुई, इसके बाद फैयाज ने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया।

दुखों के निवारण के लिए चलाया रामबाण, मस्जिद कहां से आ गई!

ओवैसी पर खूब भड़कीं बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता, तीर विवाद पर दी सफाई

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के हैदराबाद में राम नवमी के मौके पर मस्जिद के ऊपर काल्पनिक तौर से तीर चलाने के आरोपों में घिरी बीजेपी की कैंडीडेट माधवी लता ने सफाई पेश की है। माधवी लता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो को साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कल श्री राम नवमी के पावन पर्व के उपलक्ष में भाग्यनगर श्री राम नवमी उत्सव समिति के द्वारा गोशामहल विधानसभा में आयोजित शोभा यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें मेरे सभी छोटे और बड़े बहन भाइयों का जोश देखने लायक था। प्रभु श्री राम हम सभी के जीवन को सुख समृद्ध बनाएंगे। इसी पोस्ट में माधवी लता ने

वीडियो साझा करके अपने धनुष से तीर चलाने को भी दर्शाया है। माधवी लता ने कहा कि उन्होंने ऐसा दुखों से निवारण के लिए किया था। यह भगवान राम की पूजा करने का तरीका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। इसमें माधवी लता को मजिस्द की तरफ तीर चलाते हुए बताया गया था। इसके बाद हैदराबाद से लड़ रहे असुदद्दीन ओवैसी ने माधवी लता के एक्ट की आलोचना की थी और कहा था कि अगर मैं होता तो मीडिया और सभी मिलकर मेरे गले में सांप डाल देते। ओवैसी के आरोप पर माधवी ने कहा था कि मेरे संज्ञान में आया है कि मेरा एक वीडियो मीडिया में नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है।

एमपी के 20 शहरों में टेम्प्रेचर 40 डिग्री पार

सीजन में पहली बार इतनी गर्मी, दो दिन ऐसा ही मौसम, फिर आंधी-बारिश

भोपाल। बारिश, आंधी-ओले का दौर थमने के बाद मध्यप्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। गुरुवार को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर-उज्जैन समेत प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन यानी, 19 और 20 अप्रैल को गर्मी का असर रहने का अनुमान जताया है। 21 अप्रैल से अगले 3 दिन के लिए आंधी-बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन में वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) एक्टिव हो रहा है। जिसका प्रदेश में असर रहेगा। इस वजह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन भी भीगेंगे। गुरुवार को सीजन में पहली बार प्रदेश में तेज गर्मी पड़ी। सबसे गर्म धार रहा। नौगांव, गुना, शिवपुरी और धार सबसे गर्म रहे। यहां पारा 41 डिग्री से ज्यादा रहा। धार में सबसे अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बैतूल, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, खरगोन, सतना, शाजापुर, दमोह, उज्जैन, रीवा, मंडला, मलाजखंड, रतलाम, खजुराहो और नर्मदापुरम में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। 21 अप्रैलः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिलों में। 22 अप्रैलः नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में। अप्रैल में बारिश के कई रिकॉर्ड टूटे। भोपाल में करीब पौने 2 इंच बारिश हो गई। वहीं, अप्रैल में लगातार 11 दिन तक बारिश होने का रिकॉर्ड भी बना है। 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रदेश में लगातार बारिश हुई है। अब 21 अप्रैल से फिर प्रदेश भीग जाएगा।

घर पर पूजा, पत्नी से तिलक और परिवार संग सेल्फी

नामांकन भरने निकले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का अलग अंदाज

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान नामांकन भर रहे हैं। नामांकन के लिए जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि, 'मैं सौभाग्यशाली हूं कि भाजपा ने, प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने मुझे विदिशा की जनता की सेवा करने का फिर एक बार अवसर दिया है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास और अपने देश के लिए काम करने का प्रयास करूंगा।' इससे पहले विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपने आवास पर पूजा की। विदिशा की जनता के लिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि, विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र के बहनों-भाइयों, भांजे-भांजियों! मैंने अपनी संपूर्ण क्षमता से आपकी सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया है। आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर रहा हूं। इस अवसर पर आपका स्नेह, सहयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले; यही प्रार्थना है।

टैक्सी चालक ने चोरी किया था महिला डॉक्टर का पर्स, गिरफ्तार

भोपाल। टैक्सी में सवार महिला डॉक्टर का पर्स चोरी करने के आरोप में पुलिस ने टैक्सी के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पर्स भी बरामद कर लिया गया है। पर्स में नकदी और सोने के जेवर रखे हुए थे।

हनुमानगंज थाना पुलिस के मुताबिक लालघाटी के पास ग्लोबल ग्रीन कालोनी में रहने वाली 30 वर्षीय आरती वर्मा पेशे से डॉक्टर हैं। मूलतः पन्ना की रहने वाली डा. वर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें बताया कि उन्हें गृहनगर पन्ना जाना था। इसके लिए नादरा बस स्टैंड जाने के लिए उन्होंने लालघाटी से ओला टैक्सी तय की थी। ट्रैक्सी की डिक्की में उन्होंने अपना सामान रख दिया था।

पर्स में रखे थे जेवरात, नकदी- बस स्टैंड पर सामान लेकर उतरने के बाद चालक टैक्सी लेकर वहां से चला गया। उन्होंने सामान चैक किया, तो उनका पर्स गायब था। पर्स में सोने की दो अंगूठी, कान की बाली, मोबाइल फोन, दो हजार रुपये एवं वोटर आइडी रखा हुआ था। चोरी की शिकायत दर्ज कर पुलिस ने डा. वर्मा द्वारा बताए गए नंबर के आधार पर टैक्सी की तलाश शुरू की। बुधवार को सिंधी कालोनी के पास टैक्सी देखी गई, तो पुलिस ने उसके चालक को हिरासत में ले लिया। उसकी पहचान छावनी पठार आदमपुर कोलुआ निवासी 39 वर्षीय ऋषिराज चौधरी के रूप में हुई है।

बाल विवाह रुका तो नहीं हो पाई आटा-साटा प्रथा

प्रशासन ने नाबालिगों की शादी रुकवाई ; लड़के की बहन की शादी लड़की के भाई से होनी थी

भोपाल। गुरुवार देर रात प्रशासन ने गुना के गढ़ा गांव में एक बाल विवाह रुकवा दिया। लड़के और लड़की की उम्र के कोई दस्तावेज परिवार वाले पेश नहीं कर पाए। प्रशासन ने दोनों को नाबालिग मानते हुए शादी रुकवा दी। अब इस मामले में आटा-साटा प्रथा की बात भी सामने आई है। लड़की के भाई की शादी लड़के की बहन से होनी थी। इस शादी के रुकने से उनकी शादी भी रुक गई। शादी रुकने से लड़के के घरवाले अब उनकी लड़की की शादी भी नहीं करा रहे हैं। बता दें कि गढ़ा गांव में मोंगिया परिवार की लड़की की शादी कुंभराज इलाके के लड़के से तय हुई थी। गुरुवार को शादी होनी थी।

शादी की पूरी तैयारियां हो गईं थी। मंडप सज गया था। नाते रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। शादी के गीत गाए जा रहे थे। कुंभराज से लड़का बारात लेकर भी आ गया था। लेकिन इसी बीच प्रशासन को सूचना मिली कि गांव में बाल विवाह हो रहा है। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और झागर चौकी पुलिस की संयुक्त टीम गांव में पहुंच गई। टीम ने पहुंचकर लड़के से उम्र के दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा पाया। लड़के के भाई ने कहा कि घर पर कोई नहीं है और वे कोई दस्तावेज नहीं लेकर आए। टीम ने कहा कि व्हाट्सएप पर मंगा लो, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में कोई नहीं है। वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। टीम ने वहीं पंचनामा बनाया। इसी तरह लड़की के भी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह भी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। टीम ने शादी रुकवा दी। पुलिस ने भी परिवार वालों को बताया कि ये कानूनन गलत है। शादी कराई तो कानूनी कार्रवाई होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी आरबी गोयल ने बताया कि गढ़ा गांव में बाल विवाह की सूचना मिली थी। सुपरवाइजर शारदा शर्मा के नेतृत्व में टीम भेजी गई। टीम ने दस्तावेज मांगे, लेकिन परिवार वाले उम्र से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। टीम ने बाल विवाह रुकवा दिया। इस मामले में आटा साटा प्रथा की बात भी सामने आ रही है। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि उनकी लड़की की शादी कुंभराज इलाके के लड़के से तय हुई थी। इसके एवज में लड़के की बहन की शादी लड़की के भाई से होनी थी। आज बारात जानी थी। लड़की की शादी रुकवा दी गई। अब ऐसे में लड़के के परिवार वाले दूसरी शादी भी नहीं कर रहे हैं। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि लड़के वालों ने कहा कि जब तक ये शादी नहीं होगी, वो दूसरी शादी भी नहीं कराएंगे। जब तक उनके लड़के के फेरे नहीं पड़ेंगे, वह हमारे लड़के के फेरे नहीं कराएंगे।

यह है आटा-साटा प्रथा

यह प्रथा मूल रूप से राजस्थान से आई है। गुना जिले का काफी इलाका राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस प्रथा ने गुना जिले में भी पैर पसार लिए हैं। आटा-साटा प्रथा में लड़कियों की अदला-बदली की जाती है। जैसे आटा-साटा कुप्रथा के चलते किसी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ तय होती है, तो लड़की की ओर से किसी लड़के की शादी दुल्हे की बहन से तय कर दी जाती है। इस प्रक्रिया को आटा-साटा प्रथा कहते हैं। इसमें लड़की की पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती है। ऐसे में कई बार दोनों परिवार आपसी सहमति से अपनी काबिल और पढ़ी लिखी लड़कियों को अनपढ़, बेरोजगार और कभी-कभी तो बीमार और मंदबुद्धि लड़कों से शादी कर देते हैं। वैसे तो शादी के फैसले अधिकतर बड़े होने पर किए जाते हैं, लेकिन इस प्रथा के अंतर्गत कभी कभी बचपन में ही ये अदला-बदला का सौदा हो जाता है। जब वो लड़की बड़ी होती है, तब उसे इस बारे में बताया जाता है। कई बार उसे यह सदमा बरदाश्त नहीं होता है। इसके चलते लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं।

मासूमों को निगल रहे गड्ढे, अब एप से होगी निगरानी

बोरिंग असफल होने पर अपलोड करनी होगी गड्ढे की फोटो

भोपाल। खुले बोरवेल में छोटे बच्चों से गिरने की दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए अब उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के हर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नई पहल की है। एक मोबाइल एप बनवाया है। बोरवेल खोदने वाली कंपनियों के ठेकेदारों का पंजीयन अनिवार्य किया है। उन्हें गड्ढा खोदने के लिए स्थान और समय की सूचना देनी होगी। बोरवेल के सफल या असफल होने की जानकारी भी एप पर ही अपलोड करनी होगी। इससे गैर-उपयोग के गड्ढों की संख्या बढ़ने से रोका जा सकेगा। विभाग के कार्यपालन यंत्री घनश्याम उपाध्याय ने

बताया कि राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सहयोग से मोबाइल एप बनवाया है। इसके माध्यम से प्रत्येक जिले में नलकूप खनन करने वाली एजेंसियों के ठेकेदारों का अनिवार्य पंजीयन होगा। खनन के लिए स्थान और समय की सूचना देनी होगी। बोरवेल के सफल या असफल होने की सूचना देने के साथ असफल होने पर सुरक्षित रूप से बंद करने की फोटो भी अपलोड करनी होगी। बोरवेल कराने वाले व्यक्ति या संस्था को इसके सफल या असफल होने पर अक्षांश एवं देशांतर सहित फोटो के साथ जानकारी मोबाइल एप पर दर्ज करनी होगी। बोरवेल यदि असफल हो जाता है या किसी कारण से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे रेत/मिट्टी/गिट्टी आदि से जमीन स्तर पर भरकर बंद कर कांक्रीट का ब्लॉक बनाकर सुरक्षित करना होगा। इसकी जानकारी भी ऐप के माध्यम से देनी होगी। असुरक्षित खुले नलकूप की शिकायत भी मोबाइल ऐप या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से की जा सकेगी। ऐसी शिकायत पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा संज्ञान लेकर ऐसे असुरक्षित नलकूपों पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय करवाए जाएंगे। एप के माध्यम से प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध निजी एवं शासकीय, खुले एवं बंद नलकूपों की जानकारी भी संग्रहित की जाएगी। ऐप को भी प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया है। इसके बाद बोरवेल खनन कार्य से संबंधित विभागों के अधिकारियों को एप के उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर इसे विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

सागर में बोले पटवारी-बीजेपी के खाते में निकला काला धन

कांग्रेस प्रत्याशी बुंदेला की नामांकन रैली में नुक्कड़ सभा संबोधित कर वापस लौटे, नामांकन जमा कराने नहीं गए

भोपाल। लोकसभा चुनाव के चलते शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी सागर पहुंच गए हैं। वे सागर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा की नामांकन रैली में शामिल हुए। रैली में सागर व विदिशा जिले के पार्टी पदाधिकारी व वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। यहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह

समेत अन्य दोपहर 1 बजे सागर पहुंचे। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल बस स्टैंड के पास पहुंचे। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुंह अब भाजपा के नेताओं से ज्यादा चलना चाहिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार, महंगाई कम हुई क्या? घर-घर जाकर सभी कार्यकर्ता लोगों से यह सवाल करें। चायना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। यह बात उनके मंत्री ने ही स्पष्ट की है। उन्होंने भाजपा पर निशान साधते हुए कहा कि वे कहते थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसी के खाते में आए क्या? बेरोजगारी, महंगाई कम हुई क्या? उनका कहना था कि कांग्रेस नेता का काला धन बैंक में है। लेकिन अब तक काला धन नहीं आया। एसबीआई की लिस्ट आई तो पता चला कि काला धन भारतीय जनता पार्टी के खाते में था। मोदी जी कहते हैं कि मेरे आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन जब एसबीआई की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में निकले। भाजपा यह नहीं बता पाई कि यह पैसा कहां से आया। उनसे पूछा तो कहने लगे कि हमारे ऑफिस के सामने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड फेंक गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बस स्टैंड पर आयोजित नुक्कड़ सभा में शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित किया। जिसके बाद वे सभास्थल से ही वापस हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। रोड शो में वे शामिल नहीं हुए और न ही प्रत्याशी का नामांकन जमा कराने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। हालांकि रोड शो में प्रत्याशी गुड्डू राजा और अन्य कांग्रेस के नेता शामिल थे। नामांकन रैली में बड़ी संख्या में अलग-अलग विधानसभाओं के कार्यकर्ता पहुंचे।

महाकाल की भस्म आरती की बुकिंग अब 3 महीने पहले

मई के पहले हफ्ते से होगी शुरू ; तीन माह में एक ही बार मिलेगी परमीशन

भोपाल। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए भक्त 15 दिन नहीं बल्कि तीन महीने पहले बुकिंग करा सकते हैं। महाकाल मंदिर समिति इस व्यवस्था को मई के पहले हफ्ते से शुरू कर देगी। महाकाल मंदिर में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ज्यादातर भक्त सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इसकी बुकिंग 15 दिन पहले ऑनलाइन या फिर एक दिन पहले ऑफलाइन करवाना पड़ती है। ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले भक्तों के साथ ये समस्या आती है कि उनकी बुकिंग होने के बाद ही वो उज्जैन आने का प्लान तैयार कर पाते थे। इसमें उन्हें समय कम मिलता था। अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष नीरज सिंह ने भस्म आरती की ऑनलाइन प्रक्रिया में बदलाव का निर्णय लेते हुए इसे मई महीने से तीन महीने पहले खोलने का निर्णय लिया है। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि हम इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि एक आधार कार्ड एक बार उपयोग होगा। इसके बाद अगले तीन महीने तक उसे ऑनलाइन भस्म आरती की परमिशन नहीं मिल सकेगी। सॉफ्टवेयर खुद ही उसे पकड़ कर आधार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोग इसका गलत उपयोग कर बार-बार बुकिंग न करें, इसके लिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। ऑनलाइन भस्म आरती करने वालों के लिए तीन महीने पहले लिंक खुल जाएगी, जो भी श्रद्धालु फॉर्म जमा करेगा, उसे एक रिफरेंस नंबर अलॉट होगा। एक दिन बाद श्रद्धालु के पास कन्फर्मेशन लिंक जाएगी, जिसको फील करके प्रति व्यक्ति 200 रुपए जमा कर अपनी बुकिंग करवा सकेगा।

ऑनलाइन के माध्यम से एक दिन में 400 भक्तों के लिए परमिशन दी जा सकेगी। महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि तीन महीने वाला प्लान सक्सेस होगा तो इसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया जाएगा। ताकि घर बैठे भक्त अपने हिसाब से पहले मंदिर की भस्म आरती बुक कर ले, बाद में अपने रेल बस या हवाई टिकट की बुकिंग करा सकें। जल्द ही महाकाल मंदिर की वेबसाइट को अपडेट कर इसे 1 मई से शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि न सिर्फ आधार कार्ड बल्कि एक ही मोबाइल नंबर को बार-बार उपयोग कर भी ऑनलाइन परमिशन नहीं मिल पाएगी। परमिशन बुक करवाने वाले का मोबाइल नंबर के साथ-साथ भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों के मोबाइल तय सीमा में दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे भस्म आरती की परमिशन ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से होती है। ऑफलाइन परमिशन के लिए भक्तों को एक दिन पहले मंदिर में टिकट विंडो पर पहुंचकर अपनी अनुमति लेना होती है जो निशुल्क रहती है। इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से होने वाली परमिशन के लिए श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन परमिशन करवा सकते है। जिसके लिए 200 रुपए शुल्क देना होता है। साथ ही प्रोटोकॉल में भी भक्तों को परमिशन मिलती है। जिसमें अधिकारी, राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद और मीडिया का अलग-अलग कोटा है।

संपादकीय

ईवीएम और वीवीपैट : सवाल बाकी

देश में ईवीएम से चुनाव कराने को विपक्ष के संशय तथा वीवीपैट मशीनों की सभी पर्चियों की गिनती में आने वाली दिक्कतों के संदर्भ में इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब आएगा, कहना मुश्किल है। ऐसे में संभावना यही है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव वर्तमान व्यवस्था के तहत ही होंगे, क्योंकि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में दाखिल याचिका खारिज नहीं कि और चुनाव आयोग को कोई नया निर्देश दिया तो उस पर अमल तत्काल होने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लिहाजा जो भी निर्णय होगा, वो आगामी चुनावों के लिए ही हो सकता है। इस अर्थ में सुप्रीम कोर्ट यह आदेश उन विपक्षी पार्टियों के लिए तगड़ा झटका है, जो ईवीएम के बजाए चुनाव बैलेट पेपर से कराने का नरेटिव खड़ा करना चाहती थीं। वैसे भी ईवीएम के विरोध का कोई ठोस आधार विपक्ष के पास नहीं है, सिवाय इसके लिए यह प्रक्रिया शंका से परे नहीं हैं और शंका का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों की 100 प्रतिशत क्रॉस-चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एडीआर समेत अन्य वकीलों और चुनाव आयोग की दलीलें सुनी। पांच घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात साफ तौर पर कही कि हर व्यवस्था पर शक करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से मशीन से निकलने वाली पर्ची वोटर को देने को लेकर चुनाव आयोग से पूछा कि इसमें दिक्कत क्या है तो आयोग ने कहा कि मतदाताओं को वीवीपैट स्लिप देने में बहुत बड़ा जोखिम है। इससे वोट की गोपनीयता से समझौता होगा और बूथ के बाहर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कह सकते। इसके पूर्व चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अब तक जितनी वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया, उनमे से एक में भी मिस मैच नहीं हुआ। ऐसे में यह शंका करना कि वोटर द्वारा डाला वोट सम्बन्धित प्रत्याशी को न जाकर किसी और को चला गया है, केवल मनगढ़ंत बात है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम से कम 50 प्रतिशत वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। उस समय, चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 8 अप्रैल 2019 को मिलान के लिए ईवीएम संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी। लेकिन विपक्ष इससे भी संतुष्ट नहीं है। विपक्ष को अभी भी संदेह कि भाजपा लोकसभा चुनाव ईवीएम को मैनेज कर जीतना चाहती है। इसके पीछे एक कारण पीएम मोदी द्वारा एनडीए की जीत का आंकड़ा 400 पार तय करना है। इस टारगेट के पीछे आधार क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन विपक्षी पार्टियों को लग रहा है ईवीएम मैनेजमेंट से ही इतना स्पष्ट आंकड़ा प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि चुनाव में अपने वोट डलवाने और मोदी को हराने के लिए ठोस मुद्दा क्या है? उसकी ग्रास रूट लेवल तक चुनावी तैयारी कितनी है? वो कहीं नजर नहीं आती। ऐसे में ईवीएम से चुनाव का मुद्दा केवल अपनी संभावित हार का ठीकरा फोड़ने के लिए केवल सिर की तलाश ज्यादा लगता है।

बेलगाम नक्सलियों पर कसता शिकंजा

पहलू

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का संगठन अब सिमटता दिखाई दे रहा है। कांकेर में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर कर दिए। इस वर्ष अब तक 80 नक्सली मारे जा चुके हैं। अतएव भारत सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली सीमित क्षेत्र में सिमटकर रह गए हैं, जिनका जल्द सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसे दावे नए नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलियों के समूह में मारे जाने के बाद ये दावे हमेशा करती रही हैं। बावजूद माओवादी हिंसा देखने में आती रही है। इसके शिकार सुरक्षाबल और स्थानीय पुलिसकर्मी होते रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस और भाजपा के नेता भी मारे गए हैं। दरअसल सीमित क्षेत्र में सिमट जाने के बावजूद नक्सलियों को आधुनिक हथियार और दुर्गम क्षेत्रों में भी काम करने वाली संचार प्रणाली की उपलब्धता कराई जा रही है। इससे साफ होता है कि नक्सलियों की चैन अभी पूरी तरह टूटी नहीं है। इसीलिए 40 साल से नक्सलियों का कहर सुरक्षाबलों से लेकर उनकी मुखबिरी करने वाले निर्दोष लोगों पर टूटता रहा है। लेकिन बीते साढ़े तीन माह के भीतर 80 नक्सलियों का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि है और कहा जा सकता है कि सरकार और सुरक्षाबल इन्हें निर्मूल कर देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति शेष है। पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही हैं, जबकि शांति का पैगाम देकर नक्सली अपने संगठन की ताकत बढ़ाने और हथियार इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं और इनका कार्यक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाका हैं, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों, छिपने के स्थलों और जल स्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति बरकरार है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया है कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आई है, लेकिन बेनतीजा रही। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ है कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों

के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

बस्तर के इस जंगली क्षेत्र में नक्सली नेता हिडमा का बोलबाला है। वह सरकार और सुरक्षाबलों को लगातार चुनौती दे रहा है, जबकि राज्य एवं केंद्र सरकार के पास रणनीति की कमी है। यही वजह है कि नक्सली क्षेत्र में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती है तो नक्सली उसमें रोड़ा अटकाते हैं। नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूती दिख रही हैं, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश लग रहा है? बल्कि अब छत्तीसगढ़ नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन गया है। अब बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध सलवा जुडूम को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुर्तु विकासखण्ड के आदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नतीजतन नक्सलियों की महेन्द्र कर्मा से दुषमनी ठन गई। इस हमले में महेंद्र कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हरिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा अब फिर सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है।

व्यवस्था बदलने के बहाने 1967 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवाड़ी ग्राम से यह खूनी आंदोलन शुरू हुआ था। तब इसे नए विचार और राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मानवाधिकार वादियों ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने का ही पर्याय बना हुआ है। जबकि इसके मूल उद्देश्यों में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्रप्रदेश और अविभाजित मध्य-प्रदेश के आदिवासियों का कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में आदिवासियों के प्रवेश शामिल थे। किंतु विषमता और शोषण से जुड़ी भूमण्डलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देश में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया है, जो पशुपति (नेपाल) से तिरुपति (आंध्रप्रदेश) तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसरा हुआ है। जब किसी भी किस्म का चरमपंथ राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बन जाए तो जरुरी हो जाता है, कि उसे नेस्तानाबूद करने के लिए जो भी कारगर उपाय उचित हों, उनका उपयोग किया जाए?

हालांकि देश में तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ है। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता है, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता है। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायलय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती है।

राजनीति

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

नेताओं के बिगड़े बोल पर सख्ती से नियंत्रण जरूरी

लोकसभा चुनाव का प्रचार उग्र से उग्रतर होता जा रहा है। जैसे-जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आती जा रही है, प्रचार-अभियान में नफरती सोच एवं हेट स्पीच का बाजार बहुत गर्म है। राजनीति की सोच ही दूषित एवं घृणित हो गयी है। नियंत्रण और अनुशासन के बिना राजनीतिक शुचिता एवं आदर्श राजनीतिक मूल्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। नीतिगत नियंत्रण या अनुशासन लाने के लिए आवश्यक है सर्वोपरि राजनीतिक स्तर पर आदर्श स्थिति हो, तो नियंत्रण सभी स्तर पर स्वयं रहेगा और इसी से देश एक आदर्श लोकतंत्र को स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा। अक्सर चुनावों के दौर में राजनीति में बिगड़े बोल एवं नफरत की राजनीति कोई नई बात नहीं है। चर्चा में बने रहने के लिए ही सही, राजनेताओं के विवादित बयान गाहे-बगाहे सामने आ ही जाते हैं, लेकिन ऐसे बयान एक ऐसा परिवेश निर्मित करते हैं जिससे राजनेताओं एवं राजनीति के लिये घृणा पनपती है। बिगड़े बोल का दोषी मानते हुए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी एवं सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर की गई टिप्पणी को अपमानजनक मानते हुए आयोग ने सुरजेवाला के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की एवं कड़ा कदम उठाया है। लेकिन क्या इस एक्शन को सचमुच सख्त कहा जाना चाहिए? क्या आपत्तिजनक बयानबाजी और खास तौर से महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के लिए इतनी ही सजा काफी है? ये सवाल इसलिए भी कि चुनावों को हम लोकतंत्र का महोत्सव कहते आए हैं और ऐसे बयान चुनावी उत्सवप्रियता में खलल डालने वाले साबित होते हैं।

राजनीति में वाणी का संयम एवं शालीनता बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द आवाज नहीं करते, पर इनके घाव बहुत गहरे होते हैं और इनका असर भी दूर तक पहुंचता है और देर तक रहता है। इस बात को राजनेता भी अच्छी तरह जानते हैं इसके बावजूद जुबान से जहरीले बोल सामने आते ही रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हो या राजद नेता लालूप्रसाद यादव प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ कहा हो भाजपा नेता ने सोनिया-राहुल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हो, सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणियों को हेट स्पीच के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रीय एकता एवं राजनीतिक ताने-बाने को ध्वस्त कर रहे जहरीले भाषणों की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। विशेषतः महिला नेताओं एवं उम्मीदवारों पर की जा रही कथित विवादास्पद एवं अशालीन टिप्पणियां लोकतंत्र पर बदनुमा दाग बन रही है। इसी तरह सुरजवाला को हरियाणा की एक चुनावी सभा में हेमा मालिनी को लेकर की गई टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया गया है।

सुरजेवाला हो या कांग्रेस के अन्य नेता- इन सबको अपनी गलती का अहसास नहीं हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पहले बयानबाजी कर बाद में लीपापोती करने में जुटना नेताओं का शगल होता जा रहा है। ज्यादा विवाद उठने लगे तो ऐसे तीखे एवं कड़वे बयानों के वीर एवं यौद्धा यह कहकर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं कि उनके बयान को तोड़मरोड़ कर दिखाया गया है। कांग्रेस सहित अनेक राजनीतिक दलों के नेता ऐसे वक्तव्य देते हैं और विवाद बढ़ता देख बाद में सफाई देने से भी नहीं चूकते। आधुनिक तकनीकी एवं संचार-क्रांति के जमाने में हर व्यक्ति पत्रकार की भूमिका में हैं, सोशल मीडिया के दौर में जब हर हाथ में कैमरायुक्त मोबाइल रहने लगा है चुनावी सभाओं में कोई बयान सार्वजनिक हुए बिना रह ही नहीं सकता। बात केवल सुरजेवाला की ही नहीं है, इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व हिमाचल प्रदेश में मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर ऐसी ही अपमानजनक टिप्पणियां सामने आई थीं। चुनाव आयोग के संज्ञान में यह सब भी सामने आया था लेकिन बयान देने वालों को चेतावनी पत्र देकर ही छोड़ दिया गया। सुरजेवाला को लेकर आयोग के आदेश के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के इस दौर में आयोग ने किसी नेता को प्रचार से रोकने जैसा फैसला पहली बार किया है। अड़तालीस घंटे की रोक अवधि पूरी होने के बाद सुरजेवाला फिर चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि आगामी दिनों में वे अपना बर्ताव संयत रखेंगे। वे अक्सर संकीर्णता एवं राजनीति का उन्माद एवं 'हेट स्पीच' के कारण चर्चा में रहते हैं।

राजनेताओं के नफरती, अमर्यादित, उन्मादी, द्वेषमूलक और भड़काऊ भाषणों को लेकर चुनाव आयोग का सक्रिय होना नितान्त अपेक्षित है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर बिगड़े बोलो पर कड़ी टिप्पणियां की है। भाषा की मर्यादा सभी स्तर पर होनी चाहिए। कई बार आवेश में या अपनी बात कहने के चक्कर में शब्दों के चयन के स्तर पर कमी हो जाती है और इसका घातक परिणाम होता है। मुद्दों, मामलों और समस्याओं पर बात करने की बजाय जब नेता एक-दूसरे पर निजी हमले करने लगें तो यह उनकी हताशा, निराशा और कुंठा का ही परिचायक होता है। कांग्रेस पार्टी ने भाषा एवं बयानों की मर्यादा को लांघा है। दरअसल, कांग्रेस में यह रिवाज ही बन चुका है। चुनाव में वह कुछ बुनियादी समस्याओं पर बोलने की बजाय है, कोई न कोई ऐसी नफरती एवं गैरजरूरी बयानबाजी कर ही देता है जिसका परिणाम आखिरकार पार्टी को भुगतना पड़ता है। इसी कारण पार्टी लगातार जनआधार खो रही है, रसातल में धंसती जा रही है और सुरजेवाला जैसे नेताओं को सजा भी मिलती है।

पार्टी कोई सी भी हो, चुनावी सभाओं में नेता अपने विरोधियों के खिलाफ जहर उगलने से नहीं चूकते। नेता चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े हों या प्रतिपक्ष से, अक्सर भाषणों में हदें पार कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर दिए गए निर्देशों की भी इन्हें परवाह नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही चुनाव आयोग को मजबूत करने के प्रयास करते हुए उसे अपनी ताकत का अहसास भी कराया है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि कुछ गलत होने पर उसे प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकना चाहिए। चुनाव आयोग सख्ती दिखाए तो किसकी मजाल कि भरी सभाओं में जहर उगलती भाषा का इस्तेमाल कर जाए। दरअसल, इस तरह के प्रकरणों में आचार संहिता से ज्यादा नेताओं की आचरण संहिता की जरूरत रहती है। महिला हो या पुरुष, किसी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक दल आगे आकर पहल करें। आयोग से पहले खुद अपने ऐसे नेताओं पर सख्ती करे, जिनके विवादास्पद बयान चुनावी माहौल में जहर घोलने का काम करते हैं एवं नारी अस्मिता एवं अस्तित्व पर आघात करते हैं।

लोकतंत्र का महापर्व चुनाव राजनीतिक दलों एवं नेताओं के भविष्य को निर्धारित करने का दुर्लभ अवसर है। ऐसे में सोचने की बात तो यह है कि राजनीतिक भावनाओं एवं नफरती सोच को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दल भी खतरे से खाली नहीं हैं। उनका भविष्य कालिमापूर्ण है। उनकी नफरती कोशिशों पर दुनिया की नजरे टिकी हैं। वे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसी से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा दुनिया में बढ़ सकती है। जरूरत है कि हमारे राजनीति दल अपनी सोच को परिपक्व बनाये, मतभेदों को स्वीकारते हुए मनभेद को न पनपने दे। आखिर नेताओं को नफरत का बाजार सजाने की छूट क्यों हो? इस समस्या से निपटने के लिए 'हेट स्पीच' को अलग अपराध की श्रेणी में रखने के लिए कानून में संशोधन का भी वक्त आ गया है? मगर इस दौर की राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा बनता गया है कि दूसरे दलों एवं उनके नेताओं के खिलाफ नफरती भाषण देकर अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा है। निश्चित ही यह विकृत एवं घृणित सोच वोट की राजनीति का हिस्सा बनती जा रही है। इस प्रवृत्ति पर अविलंब अंकुश लगाने की आवश्यकता है ताकि इस समस्या को नासूर बनने से पहले ही इस पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके। आजादी के अमृत-काल में राजनीतिक दलों में नफरत एवं उन्माद की आंधी को नियंत्रित करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों में विनाशकारी बोलों की बजाय निर्माणात्मक बोलों का प्रचलन बढ़े।

आम, आमचुनाव, और आम बात

कटाक्ष

दिनेश गंगराड़े

लेखक व्यंग्यकार हैं।

इधर फटाक दनी से गर्मी की ऋतु आती है उधर खटाक दनी से आम आ धमकते है। हजारों आम की टोकनियों में से खासे मीठे,रसीले,सुस्वादु आम छाटना,बीनना,चुनना ही कहाता है आम चुनाव।आम आदमी, मैंगो पर्सन ही इन आम चुनावों में आम में से खास आदमी, याने अंधों में से काना व्यक्ति चुनते है। आम के बारे मे ये आम धारणा है कि इन मे रस होता है तभी इनकी अच्छी पूछपरख इन सीजन में बनी रहती है। गर ये नीरस, बेस्वाद, खट्टे होते तो हर मैंगो पर्सन इन फलों के राजा को क्यूँ घास डालते।आमों के बारे में अक्सर बका जाता है कि वे फ्रूट किंग है। जभी तो मैंगो ज्यूस बहुत महंगा पर स्वादिष्ट है। ये इतने प्रिय होते हैं कि लोग इसके छिलके तक खा जाते है, गुठली को भी इतना चूसते है कि उसे निन्यानवे फीसदी सुखा देते है?आमों का डेमोक्रेसी से कोई लीजे-दीजे नही है पर देश मे जब भी नेता चयन का मुआमला आता है तो आम सबसे पहले आ टपकते है। गोल मटोल आम होते तो नेता की तौंद की मानिंद है पर ये रसदार और वें रसहीन,होते है। आम के आम पर इनकी गुठलियों के भी दाम,उसूल होते है लेकिन नेता के न दाम न ही कोई उसूल होते है।एक आम को देखकर दूसरा पकता है,सड़ता है किंतु नेता गिरगिट सा रंग बदलता है।ज्यादा एकत्रित होने पर कुर्सियां फैकता है,चीखता है,चिल्लाता है,सिर फोड़ता है। रस के मामले में आम फलों का राजा है चाहे वो लंगड़ा हो,हापुस हो,दसेरी हो पर इंसान तो न मन का राजा है न ही जन-जन का?आम की आमियत विश्व विख्यात है परंतु नेता की नीयत कुख्यात होती है। बंदे को आम भोत पसंद है क्योंकि मेरे दादा आम का पेड़ लगा के निपट गए थे और मैं आज भी छाती ठोंक के बोम दे सकता हूँ कि ढिमका गांव में मेरे बाप-दादा के आम गड़े है। इस गड़ने की बात पर कुछ लोगों ने अपना उपनाम आमगड़े,जाम गड़े धर लिया। जैसे सच्चाई नही छुप सकती बनाबट के उसूलों से वैसे ही आम की खुशबू लाख छुपा कर रखो फिर भी कतई नही छिप सकती है,दब सकती है तभी बचपन मे मेरे घर जब आम की पाल रखते थे तो ये आम का दीवाना उसकी पकास ढूढ़ लेता था।इस गर्मीले मौसम में आम की खुशबू,यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त हो कर अपनी मौजूदगी बिखेर रही है। अमिया,कच्ची केरी, केरी, पक्की केरी अब अमियाने लगी है,पूर्ण आम बन चली है।आम की दादागिरी सदियों से बदस्तूर जारी है और रहेगी। आम, यू तो हैआम,सरेआम,खुलेआम, पर अमराइयों में इनकी खुशबू मचा देती है कत्लेआम। सैकड़ों सालों से कोई साला इनका बाल भी नहीं बांका कर सका है न ही उखाड़ पाया है। एक आम प्रेमी ने कहा-आम गधे भी नहीं खाते।

दूसरे ने कहा-आम सिर्फ गधे ही नहीं खाते है। मुगल सम्राट अकबर को तो आम इतना पसंद था कि जब उसका सीजन नही होता था तो वह दूसरों की दाढ़ी चाशनी में डुबोकर चूसा करता था। अब आम इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी की बिसात ही क्या जो वो ये आम सहजता से क्रय कर नही चूस सकता है। आम,आमफल न हो कर खास फ्रूट बन गया है।आमों के बारे में आम धारणा है कि ये एक-दूजे को देखकर रंग बदलते है,पकते है,खुशबू मारते है।आम की आमेंली खुशबू तो मैंने अपने घर की आम के पाल में महसूस की पर गिरगिट सा आमों को रंग बदलते नही देखा,जैसा इस मैंगो इलेक्शन में नेताओं को निहार रहा हूँ।

साहित्य में भी आम आदमी का व्यंग्य सब पसंद करते हैं। दुनिया में सिर्फ आम का वृक्ष ही ऐसा है जो पत्थर मारने पर भी प्रतिफल में मीठा फल देता है। किसी मसखरे का कहना है कि दशहरे के दिन ये फल खाया होगा तो नामकरण हुआ दशहरी आम। आम के बारे में नोकटालीजिया रहता है कि हमारे जमाने में टोकरी भर आम खरीदे जाते थे। आम के भावों की अराजकता से बाजार तो खुश है,व्यापारी खुशनुमा किंतु गरीबड़ा अटाटूट ग़मगीन है। आम जैसे फल को आम, सरेआम, खुलेआम आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा पर अपुन के चाहने से क्या होगा।अपन की कोई अमराई थोड़ा है। किसी शायर ने कहा है-आम तेरी ये खुशनसीबी है वरना लँगड़े पे कौन मरता है? हराम-जमाखोर,कमीशन खोर,सालें जाए भाड़ में इनका हो कत्लेआम किंतु आम,खुलेआम नसीब हो आम ओ खास को ये आम,आम्र।इस भनभनाट गर्मी में सुलभ हो आम और आम आदमी, आम लोगों में से ही चुने खास आदमी,और बने आम सरकार।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

नंदकिशोर बर्वे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सूत भी कपास भी

जब सूत भी हो और कपास भी। तब जुलाहों में लट्ठमलट्ठा होना उतना अस्वाभाविक नहीं है जितना इनके न होने पर! पर दुनिया वालों को तो किसी की भी जगहंसाई का कारण चाहिए बस। सूत और कपास के अभाव में जब लट्ठ चलते हों, तो इस पर तो हंसना बनता है, लेकिन जब सूत और कपास पूरी शिद्दत से अपनी उपस्थिति की ताल ठोक रहे हों, तब तो जुलाहों में जो भी हो सकता है, वह तो होगा ही। होना भी चाहिए।

अब यह तो जगजाहिर है कि कपास से सूत बनता है। सूत से धागा। धागे से ही आगे चल कर जनेऊ और टोपियाँ। लेकिन यह सबसे बड़ी मुश्किल है कि एक ही तरह के कपास से बनी जनेऊ और टोपियाँ परस्पर असहिष्णु होती हैं। जो अपने मूल से कटा उसका यही हाल होता है ध्यान रहे। इसलिए अपने मूल, जड़ और जमीन से जुड़े रहने के अपने फायदे हैं। और ऊपर तले के अपने खतरे।

जो जुलाहे हैं, उनका मूल काम है बुनना। लेकिन वह समय निकल गया जब वे केवल अपने काम से काम रखते थे। याने केवल बुनाई ही किया करते थे। अब तो जुलाहे बुनाई कम धुलाई कमाई और चढ़ाई ज्यादा करते हैं। जिसे मौका मिला, दूसरे पर चढ़ लिये। और चढ़ाई भी ऐसी कि जो जिस पर चढ़ लिया, वह चढ़ा ही रहता है। उतरने का नाम लिया, कि बेताल की तरह खा जाने को दौड़ता है। तो इन दिनों लट्ठम लट्ठा से लेकर जूती पैज़ार होने तक का मौसम अपने पूरे शबाब पर है। इसलिए राजनितिक जुलाहे, बुनने का काम पूरी तरह छोड़कर लट्ठमारी में लगे हैं। जब चुनाव का कपास और प्रचार का सूत भरपूर मात्रा में हो, तो होना तो यह चाहिए कि जनता का मन बुनने का काम करें। 'झीनी चदरिया' न ही सही, मोटी पतली कैसी भी बुनें। पर बुनें तो। लेकिन इस तरह के कपास से बुनाई कम, उधेड़ने का काम ज्यादा होता है। वह इसे उधेड़ रहा है, यह उसे। सब पर उधेड़ने की उधेड़बुन सवार रहती है।

जरूरी नहीं कि लट्ठ केवल लट्ठमारी के ही काम में लिया जाए। उसके रचनात्मक उपयोग भी हो सकते हैं। जैसे कि झंडा लगाना, झंडा फहराना। और सबसे बढ़कर तो गिरते का सहारा हो सकता है लट्ठ। कहा नहीं गया बुढ़ापे की लाठी है, वह तो। पर पता नहीं कैसा समय है? रचनात्मकता तो सिर से सींग की तरह गायब हो गई है। बिना सींग के प्राणी ही प्राणी रह गए हैं, इन जुलाहों के रूप में। अब जब सूत और कपास पास है, तो चदरिया बुनो। बुनोगे तभी तो जस की तस धर पाओगे। पर आज जस की तस धर कर , कौन गैर दुनियादार बनना चाहेगा ? कह नहीं सकते कि दास कबीर आज होते, तो वे भी जस की तस धर पाते या नहीं !

'कपास और सूत तो आपके पास इफराती में है, फिर भी आप बुनने के बजाय लट्ठ मारी में क्यों उलझे हुए हैं ?' मैंने एक जुलाहे से पूछा।

'बुनने काम तो कभी भी हो सकता है, लेकिन लट्ठ बाजी का अपना समय होता है। उसी समय करनी होती है जब सब कर रहे हों। एक बार इस लट्ठमारी में बाजी हाथ लगी तो पांच साल बुनना और बनाना ही है।' वे बोले।

'आपके पास तो पहले भी अवसर रहे हैं। उस समय भी मुझे लगता है आप मनचाहा बुन नहीं पाए।' मैंने कुरेदा।

'अरे कहाँ ? बुनने का काम तो रोज कुआँ खोदो रोज़ पानी पियो जैसा है। चदरिया कितनी भी लम्बी हो बुनने का काम तो जारी रहता है। इसलिए बुनने से कैसा बचना?'

मैं कुछ और पूछने ही जा रहा था कि एक नये आरोप की लाठी उन पर पड़ी। और वे उससे बच नहीं पाए। फिर प्रत्यारोप और प्रति आक्रमण की लाठी लेकर निकल गए। अब लट्ठ बाजी नए सिरे से जारी है।

आर्थिकी

शिवेश प्रताप

लेखक तकनीकी प्रबंध सलाहकार हैं।

असमानता, बेरोजगारी, रोजगार एवं कौशल गुणवत्ता की समस्या

वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बाद अब हम घरेलू अर्थव्यवस्था की चुनौतियों पर दृष्टि डालें तो सबसे बड़ी समस्या असमानता है। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को अत्यधिक आसमान देशों की लिस्ट में रखा गया है। भारत के शीर्ष 10 प्रतिशत लोग, देश के 57 प्रतिशत संपदाओं के मालिक हैं। 50 प्रतिशत आबादी के पास मात्र 13 प्रतिशत संपदा है। लेकिन इस असमानता की स्थिति की गहराई में जाएं तो इसके कई मूल कारण दिखाई देंगे जैसे बेरोजगारी, रोजगार की गुणवत्ता में कमी तथा कौशल विकास एवं नवाचारों में कमी।

इन विषयों को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय आर्थिक विकास नीति को गहराई से समझाना पड़ेगा। भारत ने देश के आजाद होने के बाद एक ऐसे मिले-जुले आर्थिक ढांचे को स्वीकार किया जिसमें सरकार अग्रणी की भूमिका में रही एवं निजी क्षेत्र को बेहद सीमित अधिकार दिए गए। सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलते हुए भारत सरकार आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए उत्तरदाई थी एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्णय लिया जाता था कि देश के मानव संसाधन को किस क्षेत्र में लगाया जाएगा।

देश की आजादी के समय भारत एक कृषि आधारित देश था एवं देश की अधिकतर जनसंख्या खेती-बाड़ी के कामों में लगी रहती थी। तत्कालीन नेहरू सरकार ने विनिर्माण एवं भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे पंडित नेहरू का विचार था कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भारी उद्योगों का विकास आवश्यक है। और इस तरह से इस विकास का लाभ ऊपर से नीचे की ओर स्वयं जाएगा। विकास की जी अधोमुखी अवधारणा पर नेहरू जी ने भारत के आर्थिक विकास का स्वप्न देखा उसे वास्तव में सरकार के अधिकारी नियंत्रित कर रहे थे। अंततोगत्वा भ्रष्टाचार एवं लाल फिताशाही के चलते योजना के अनुरूप लाभ कभी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं सका। इसी के साथ भारी उद्योग के निर्माण में देश ने इतनी अत्यधिक पूंजी लगाई की शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र में निवेश के लिए संसाधन बहुत कम बचे।

भारत में कौशल विकास

आजादी के बाद बनी विकास की योजनाओं में इस बात को भुला दिया गया कि एक कृषि आधारित समाज को शिक्षा के द्वारा ही भारी उद्योग आधारित कल कारखानों में नौकरियां मिलेंगी। साथ ही कृषि जिस पर देश की अधिकतर जनता का जीवन निर्भर करता था उसे क्षेत्र को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। इसके फल स्वरुप देश के पढ़े लिखे समाज ने उद्योगों में तेजी से नौकरियां तो हथिया लिया परंतु कृषि पर जीवन ज्ञापन करने वाले लोग शिक्षा के अभाव में गरीब के गरीब बने रहे। 1980 90 के दशक में अंत सरकारों को इस भारी गलती का एहसास हुआ और कृषि को अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाने का निर्णय लिया गया। परंतु इस फैसले को क्रियान्वित करने के क्रम में देश लगभग 40 वर्ष पीछे चला गया। साथ ही कृषि पर जीवन यापन करने वाली एक बहुत बड़ी जनता द्वारा सरकार की योजनाओं एवं सुधारो पर से विश्वास भी उठ गया।

भारत में कौशल विकास की स्थिति एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में स्थापित है। मोदी सरकार के लगातार प्रयासों से आज भारत में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है परंतु यदि फिनटेक एवं फार्मास्यूटिकल को छोड़ दिया जाए तो भारतीय नवाचारों के द्वारा कोई ऐसा क्रांतिकारी बदलाव घरेलू मार्केट में नहीं आया है जिससे इंटेल, एप्पल या गूगल जैसी क्रांति खड़ी की जा सके। भारत को नवाचारों की दिशा में अभी बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। कुल मिलाकर नवाचारों की कमी कौशल विकास की कमी तथा बेरोजगारी एक दूसरे से अंतर संबंधित विषय हैं जिनका स्थाई समाधान शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में बड़े निवेश के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मोदी सरकार के आगामी कार्यकाल में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की अपेक्षा है।

अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च

विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जीडीपी का 0.66 प्रतिशत अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करता है जो विश्व औसत 2.63 प्रतिशत से चिंताजनक रूप से बहुत कम है। इजरायल अपने जीडीपी का 5.5 प्रतिशत तथा अमेरिका 3.5 प्रतिशत

अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर खर्च करता है। इन सभी समस्याओं को हल करने का रास्ता औद्योगिक विकास से होकर गुजरता है और इसलिए भारत सरकार चैतन्य होकर इस दिशा में कार्य कर रही है। इसी प्रयासों के क्रम में विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों जैसे एप्पल, लोकहिड मार्टिन, सैमसंग, एअरबस आदि भारत में अपने विनिर्माण इकाई बना रहे हैं। इन सभी के द्वारा भारत में अनुसंधान एवं विकास को गति मिलेगी। साथ ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी अपनी शैशव अवस्था से है जो आगामी 10 वर्षों में एक बड़े क्रांति के रूप में विश्व मंच पर दिखाई देगा। वर्तमान में ड्रोन विनिर्माण तथा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित स्टार्टअप्स को सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रमोट किया जा रहा है। परंतु सकारात्मक क्रांति के लिए भारत को अनुसंधान एवं विकास पर अपने जीडीपी का दो प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। कौशल विकास के माध्यम से जिन नई तकनीकियों पर युवाओं को कुशल बनाने की आवश्यकता है उसमें अभी भी संयोजन की समस्याएं आ रही हैं जैसे ट्रेनिंग संस्थाओं एवं उद्योगों के बीच समन्वय न होने के कारण युवाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू

वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कई सकारात्मक पहलू हैं जिनसे 1991 के बाद देश की आर्थिक प्रगति के साथ देशवासी रूबरू हुए। परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिनसे हमें समय-समय पर दो-चार होना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा उछाल तो दिया परंतु इसी वैश्वीकरण के कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ गई है तथा दुनिया के दूसरे गोलार्ध में भी कोई नकारात्मक आर्थिक गतिविधि दुनिया के सभी देशों को कमोबेश प्रभावित करता है। वर्तमान में जब विश्व के कई देश मंदी की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे भंगुर वैश्विक आर्थिक स्थितियों में यह स्थिरता भारत की आर्थिक गतिविधि के लिए एक शक्तिशाली संकट बन सकता है। वैश्विक स्तर पर एक लंबे समय के बाद आर्थिक मंदी की वापसी हुई है। भारत जैसे विकासशील देशों में सामान्य से उच्च मुद्रा स्फीति एक सामान्य घटना बनी रहती है जिसके अपने नफे नुकसान भी हैं। चिंताजनक बात यह है कि आज अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के सभी बड़े देशों में मुद्रास्फीति की स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों से भी विकराल हो गई है। मुद्रास्फीति महंगाई को आमंत्रित करता है जिससे एक सामान्य व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। विश्व विकसित देशों की मुद्रा स्थिति के कारण भारत के निर्यात में एक गिरावट दर्ज की गई साथ ही आयत में बढ़ोतरी हो गई है जो चिंताजनक है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वैश्वीकरण के इस दौर में भारत के 'विश्व का कल्याण हो' की प्रार्थना की प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है। कैसे संपूर्ण विश्व वैश्वीकरण के दौर में एक गांव बन गया है जहां सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं इसलिए सभी को एक दूसरे के कल्याण की बात सोचनी पड़ेगी। इसी विश्व के कल्याण के अंतर्गत रूस एवं यूक्रेन के युद्ध ने पूरे विश्व की आर्थिक मंदी के दौर में कोढ़ में खाज का काम किया है।

अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया है जिसका प्रभाव भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर नकारात्मक रूप से पड़ा है। साथ ही इसका दुष्प्रभाव मौद्रिक विनिमय पर भी पड़ता है और रुपया कमजोर होने लगता है। अभी हाल ही में एक्स एवं फेसबुक जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भारत में कर्मचारियों की छटनी किया है साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी विदेशी निवेश कम प्राप्त हो रहा है।

इन सभी जटिल परिस्थितियों में मोदी सरकार के द्वारा बहुत सूझबूझ से कदम रखते हुए 'आपदा में अवसर' तथा 'वोकल फॉर लोकल' का नारा दिया गया है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्थितियां से संगरोध करने के लिए अपने घरेलू बाजारों की ओर मुड़ना होगा। वैश्विक बाजारों से आत्मनिर्भरता को कम करना होगा। निवेश के लिए आम जनता के पैसों को बैंक खातों से निकाल कर स्टॉक मार्केट तक लाना होगा जिससे विदेशी निवेशकों पर निर्भरता को निर्णायक रूप से कम किया जा सके। इसी के साथ भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के स्थान पर नई रणनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित करनी होगी। 21वीं शताब्दी को एशिया की शताब्दी कहा गया है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस एशिया की शताब्दी का नेतृत्व भारत के हाथों में रहे। 75 वर्षों के अंतराल में हमने अपने कॉलोनाइजर को पीछे छोड़ विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक नज़ीर कायम किया है। अब हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी करना है।

आम चुनाव 2024

बाल मुकुन्द ओझा

लेखक स्तंभकार हैं।

विपक्ष को फिर सताया ईवीएम का डर

ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत में पहुँच गया है। सर्वोच्च न्यायलय ने चुनावों में ईवीएम के डाटा से वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान की मांग पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय ने कहा कि आप हर चीज पर अविश्वास नहीं जता सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईवीएम की आलोचना और मतपत्रों को वापस लाने का आह्वान करने के कदम पर नाखुशी जताई है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की आशंका से साफ इनकार किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उस आरोप की जांच की जाए जिसमें बताया गया है कि केरल में ईवीएम के मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने ईवीएम और वीवीपएटी के पर्ची के मिलान से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यह मामला उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसे चेक करे। इसी बीच लोकसभा की 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया। शेष सीटों पर चरणबद्ध मतदान संपन्न होगा। इसी के साथ ईवीएम को लेकर सियासत गर्माने लगी है। विशेषकर जब से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है तब से विपक्ष की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। कांग्रेस के नेता ऊलजलूल बयान भी देने लगे है। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे कह रहे है मोदी जीता तो यह अंतिम चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन के नाम से एकजुट हुआ विपक्ष लोकसभा चुनाव आते ही बिखरने लगा है। उसके घटक दल एक एक कर उसका साथ छोड़ने लगे है। मोदी के 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर संदेह व्यक्त करने लगी है। ऐसा लगता है विपक्ष को लोकसभा चुनाव में संभावित हार का डर सताने लगा है। इसलिए अभी से ईवीएम पर अंगुली उठाई जाने लगी है। यह स्थिति तो तब है जब भारत निर्वाचन आयोग सहित देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा ईवीएम को विधिमान्य ठहराया जा चुका है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि ईंडिया गठबंधन की पार्टियां का मानना है कि ईवीएम की

अखंडता पर कई संदेह है। हम मतपत्र प्रणाली के दोबारा इस्तेमाल की मांग करते हैं। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। लोगों में विश्वास बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल बैलट से चुनाव कराने की मांग कर रहे है। दिग्विजय सिंह सरीखे नेता तो खुलमखुला ईवीएम का विरोध करते है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पांच राज्यों के आए नतीजों के बाद एक बार फिर से विपक्ष ने अपनी हार ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट से चुनाव कराने की मांग की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में ईवीएम के जरिए अलग-अलग राज्यों के 140 से ज्यादा विधानसभा चुनाव कराए जा चुके है। इनमें से करीब 33 चुनावों में अब तक कांग्रेस जीती है जबकि करीब 29 चुनाव भाजपा ने जीते है। भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल से शुरू हुआ था। फिर 1999 में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ स्थानों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। यानी 2004 के पहले तक ईवीएम और बैलेट दोनों से चुनाव कराया जाने लगा, लेकिन 2004 लोकसभा चुनाव का ईवीएम से कराया था। अब पूरे देश में ईवीएम के जरिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। 2004 से 2019 तक 4 लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुए हैं। इसमें 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी जीती है।

भारत में अब प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ही संपन्न होती है। पुराने कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) मतों को दर्ज करने का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो इकाइयों से बनी होती हैं - एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट - जो पाँच-मीटर केबल से जुड़ी होती हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है और बैलेट यूनिट को मतदान कम्पार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। मतपत्र जारी करने के बजाय, कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर मतपत्र बटन दबाकर एक मतपत्र जारी करेंगे। इससे मतदाता अपनी पसंद के अभ्यर्थी और प्रतीक के सामने बैलेट यूनिट पर नीले बटन को दबाकर अपना वोट डाल सकेगा।

क्रियान्वयन

मोहन लाल गमेती

लेखक तकनीकी प्रबंध सलाहकार हैं।

बढ़ने लगी है सरकारी योजनाओं की पहुंच

'हर में हर महीने की पहली से तीन तारीख के बीच राशन मिल जाता है. यदि कभी लेट होता है तो मेरे पोता और पोती राशन डीलर से नहीं मिलने का कारण पूछते हैं. मुझे तो कुछ नहीं पता है लेकिन मेरे घर की नई पीढ़ी बहुत जागरूक है. बच्चों ने राशन से संबंधित सभी दस्तावेज़ जमा करा रखा है. इसलिए हमारा राशन नहीं रुकता है. अब तो मेरी पेंशन भी समय पर मिलने लगी है. सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों के कारण मिलने लगा है. वह योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं और फिर पंचायत कार्यालय में जाकर उसे शुरू कराने का आवेदन देते हैं.' यह कहना है 76 वर्षीय अम्बा बाई का, जो राजस्थान के उदयपुर जिला स्थित लोयरा गांव की रहने वाली है.

ऐतिहासिक नगरी उदयपुर से मात्र 8 किमी की दूरी पर आबाद यह गांव बडग़ांव तहसील के अंतर्गत आता है. अनुसूचित जनजाति बहुल इस गांव की जनसंख्या करीब 2500 है. गांव में 550 मकानों में कुछ ओबीसी से जुड़े डांगी समुदाय के साथ साथ कुछ घर लोहार, जाट, सुथार और उच्च जातियों की भी है. उदयपुर शहर से करीब होने का प्रभाव गांव में साफ़ नज़र आता है. कुछ कच्चे मकानों को छोड़कर अधिकतर मकान पक्के बनने लगे हैं. हालांकि आर्थिक रूप से अभी भी यह गांव कमज़ोर नज़र आता है. ओबीसी और सामान्य जातियों के लोग जहां कृषि, व्यवसाय और पशुपालन करते हैं वहीं अनुसूचित जनजातियों से जुड़े अधिकतर परिवार के पुरुष सदस्य उदयपुर शहर के आसपास संचालित मार्बल फैक्ट्रियों में लेबर वर्कर के रूप में काम करते हैं. कुछ दैनिक मज़दूर के रूप में भी काम करते हैं. वहीं कुछ परिवार के पुरुष सदस्य अहमदाबाद, सूरत और बेंगलुरु के फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं. जबकि घर की महिलाएं शहर के बड़े घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं.

आर्थिक रूप से लोयरा गांव भले ही कमज़ोर हो, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यह गांव पहले की अपेक्षा अधिक विकसित होने लगा है. यही कारण है कि गांव में सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है और वह इसका अधिक से अधिक लाभ भी उठाने लगे हैं. गांव की नई पीढ़ी में शिक्षा का स्तर बढ़ा है. अनुसूचित जनजाति समुदाय के लड़के और लड़कियां भी 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं. शिक्षा के बढ़ते स्तर ने गांव में जागरूकता को बढ़ाने का भी काम किया है. इसकी मिसाल खाद्य सुरक्षा के तहत गांव में मिलने वाली जन वितरण प्रणाली का लाभ है. इस संबंध में 45 वर्षीय शिवलाल कहते हैं कि वह स्वयं 12वीं पास हैं और बेंगलुरु जाकर मार्बल फैक्ट्री में काम करते हैं. लेकिन गांव में सरकार द्वारा दी जाने वाली लगभग सभी योजनाओं की न केवल उन्हें जानकारी है बल्कि उनका परिवार इसका लाभ भी उठाता है. वह बताते हैं कि 'पहले के समय में राशन डीलर कुछ बहाना करके हमें राशन से वंचित कर देता था. लेकिन अब शिक्षा और जागरूकता के कारण ऐसा संभव नहीं है. अब राशन नहीं मिलने पर हम उससे सवाल करते हैं. पंचायत कार्यालय जाकर जानकारियां प्राप्त करते हैं. मैं जब घर पर नहीं होता हूं तो मेरे बच्चे यह काम करते हैं. इसलिए अब समय पर हमारा राशन मिल जाता है.'

गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग तारु बाई कहती हैं कि 'अब हमारे समुदाय की 55 प्रतिशत लड़कियां 12वीं तक पढ़ने लगी हैं. इसीलिए उन्हें सभी योजनाओं की जानकारियां हैं. घर में बच्चों के पढ़ने के कारण ही मेरी

वृद्धा पेंशन शुरू हो सकी है. उन्होंने ही मेरे सारे कागज़ात जमा कराये. जबकि हमारे समय में लड़कियों के पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था. इसलिए हमें किसी सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ पता नहीं होता था. कभी किसी से किसी योजना का नाम सुना और जब उसके बारे में पंचायत में पता भी किया तो कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था. लेकिन अब नई पीढ़ी सभी योजनाओं के बारे में जानने लगी है. उन्हें यह भी पता है कि इसका लाभ उठाने के लिए कौन सा फॉर्म भरने की आवश्यकता है.' तारु बाई बताती है कि 'गांव का अधिकतर अनुसूचित जनजाति परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है. अधिकतर परिवारों के पास इतने पैसे नहीं है कि वह कोई व्यवसाय कर सकें और न ही इतनी ज़मीन है कि वह उस पर खेती या सब्ज़ी उत्पादन कर सकें. नई पीढ़ी पढ़ने तो लगी है लेकिन नाममात्र लोग ही नौकरी करते हैं. इसीलिए इस समुदाय के ज़्यादातर सदस्य मज़दूरी या फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं. लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के प्रति नई पीढ़ी में उत्साह है.'

55 वर्षीय सुंदर बाई बताती हैं कि 'मेरे 5 बच्चे हैं और सभी स्कूल जाते हैं. बड़ी बेटी पिछले वर्ष 12वीं पास की है और अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है. मुझे अपनी बेटी के माध्यम से पता चला कि सरकार हमारे समुदाय के उत्थान के लिए बहुत काम करती है. ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठा कर हम अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग विकास कर सकते हैं. मेरी बेटी ने भी इसका लाभ उठाते हुए स्कॉलरशिप प्राप्त किया है. मैं और मेरे पति पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए पहले राशन डीलर किसी न किसी कागज़ की कमी बता कर हमारा राशन रोक देता था. लेकिन जब मेरी बेटी ने जाकर उससे बात की और खुद से सरकारी वेबसाइट पर सारे कागज़ात भरे, इसके बाद से हमारा राशन कभी नहीं रुका है. हमें खुशी है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं. इसीलिए समुदाय के अधिकतर लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं. हालांकि हमारे समुदाय के नाममात्र बच्चे ही सरकारी नौकरियों में हैं. लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार बच्चों में पढ़ने लिखने का रुझान बढ़ा है और उनमें जागरूकता आई है, उससे वह भी जल्द ही सरकारी नौकरी में भर्ती होने लगेंगे.'

हालांकि इसी गांव में मांगी लाल और तुलसीराम का परिवार भी है जो खाद्य सुरक्षा के तहत जन वितरण प्रणाली का लाभ उठाने से वंचित है. मांगी लाल के पुत्र भूपेंद्र 12 वीं पास है. उनका कहना है कि उनके परिवार में 7 सदस्य हैं. पिछले वर्ष उनका राशन BPL से APL में कर दिया गया. जिससे उन्हें राशन मिलना बंद हो गया है. इसके लिए वह लगातार ई-मित्र से बात कर रहे हैं. वहीं तुलसीराम कहते हैं कि कुछ दस्तावेज़ की कमी के कारण उनके परिवार को राशन नहीं मिल रहा है. जिसे वह जल्द ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं. बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ते प्रसार ने लोयरा गांव के अनुसूचित जनजाति समाज को भी जागरूक बना दिया है. जिसका परिणाम है कि पिछड़ा समझे जाने वाले इस समुदाय की भी सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ने लगी है. (चरखा फीचर)

सड़क बनी सब्जी बाजार, लोगों का चलना हुआ दुश्वार

सड़क पर वाहनों की पार्किंग, नहीं रहती ट्रैफिक पुलिस

संजय द्विवेदी बैतूल।

शहर इन दिनों अतिक्रमण के हमले की चपेट में है। चुनाव में व्यस्त शासन-प्रशासन के द्वारा इस पर ध्यान न देने से फुटपाथ पर पैदल चलना और सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर स्थिति तब और खराब हो जाती है जब सब्जी बाजार का दिन होता है। पूरा बाजार नगरपालिका और यातायात पुलिस को धता बताकर सड़क पर ही लगता है।

साप्ताहिक बाजार के दिन रोड से निकलना दूभर – बैतूल में सब्जी का कारोबार बढ़ता जा रहा है, पर नपा पार्किंग, बाजार लगाने सहित अन्य इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसका खामियाजा लोगों सहित वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। बाजार में लोग घुस तो जाते हैं, लेकिन वाहन खड़े करने की जगह नहीं रहती, सब्जी खरीदने से लेकर बाजार से बाहर निकलने तक में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इधर सदर साप्ताहिक बाजार में सडक़ पर ही वाहनों की पार्किंग की जाती है। इससे नेशनल हाइवे पर जाने वाले बड़े वाहनों, खासकर बस-टक को निकलने तक की जगह नहीं बचती। ऐसे में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साप्ताहिक बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए बाजार में कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती है। इससे आम लोगों को खुद ही ट्रैफिक व्यवस्था बनाना पड़ता है। शहर में कोठीबाजार और सदर क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार रविवार और गुरुवार को लगते थे। दोनों ही जगह बाजार लगने पर लोगों को निकलना मुश्किल होता है। सडक़ पर लगने वाले बाजार में बार-बार जाम के हालात बनते है। खास कर रविवार को सदर बाजार में वाहनों की पार्किंग मेन सडक़ तक आ जाती, जिससे बस, ट्रक सहित अन्य वाहनों का निकलना ही मुश्किल हो जाता। यह बाजार पहले सिमटा हुआ था, लेकिन धीरे-धीर बढते ही जा रहा है। अधिकांश जगहों पर सडक़ें पीडब्ल्यूडी की हैं लेकिन बिना एनओसी के ही सडक़ पर ये बाजार लगते हैं।

व्यवस्था बनाने नपा डालती चूने की लाइन, पर व्यापारी सड़क किनारे बैठ बेचते हैं सब्जी, नतीजा ट्रैफिक जाम – नपा बाजार को व्यवस्थित करने के लिए समय-समय पर चूने की लाइनिंग डलवाती है, एक दो दिन तो इसका पालन भी होता है। चूने की लाइनिंग के पीछे दुकाने लगाने की व्यवस्था की जाती है लेकिन इसके बाद हालात पहले की तरह हो जाते हैं। चूने की लाइनिंग को क्रॉस करके व्यापारी सडक़ पर ही बैठने लगते हैं। सदर में किसी समय नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पीछे पार्किंग बनाई गई थी। लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया। अब सडक़ पर हो बीच में वाहन खड़े होते हैं। यहां पर ट्रैफिक पुलिस का अमला भी नहीं रहता है इससे बस-टक समेत अन्य वाहनों को भी निकलने में कई बार भारी परेशानी होती है।

बाजार शिफ्टिंग के नहीं किए नगरपालिका ने कोई प्रयास – काली चट्टान कालापाठा का बाजार सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है, वहां लाइट्स तक नहीं है, शाम और रात को सबसे ज्यादा अव्यवस्था कालापाठा काली चट्टान के बाजार में लोगों को होती है। यह बाजार उबड़-खाबड़ चट्टानों के बीच सब्जी दुकान लगाकर लगाया जाता है। इन्हीं चट्टानों के बीच जैसे-तैसे व्यवस्थाएं बनाकर सब्जी वाले बैठने की जगह बनाते हैं और दुकानें लगाते हैं। इस बाजार में पार्किंग के इंतजाम नहीं है। भग्गूढ़ाता की ओर जाने वाली सडक़ पर ही लोगों को यहां-वहां वाहन खड़े करने पड़ते हैं। जब बाजार करके लोग वापस आते हैं तो उन्हें वाहन निकालने में काफी परेशानियां होती हैं।

शहर के इन बाजारों में पार्किंग की दिक्कत

कोठीबाजार साप्ताहिक सब्जी बाजार में रविवार और गुरुवार को सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। यह बाजार अब कोतवाली चौक से टिकारी तक, कमानी गेट के पास तक फैल गया है। यहां पार्किंग के इंतजाम नहीं है सडक़ पर ही वाहन खड़े करके लोग सब्जी खरीदते हैं।

गंज में भगवान परशुराम चौक से बाबू चौक तक की पूरी सड़क पर अब बाजार लगने लगा है। हालांकि सडक़ काफी चौड़ी है, लेकिन फिर भी इस पर वाहन खड़े होने से परेशानियां होती हैं। यहां भी सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग होती है।

10 साल में 556 से 1400 रुपए हुआ सब्जी कारोबारी

शहर में नगरपालिका क्षेत्र में सब्जी व्यापारियों की संख्या 10 साल में तीन गुनी हो गयी है। 10 साल पहले 556 सब्जी व्यापारी नपा के रिकार्ड में रजिस्टर्ड थे। लेकिन 10 सालों में इनकी संख्या बढ़ती हुई 1400 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा संख्या 2020 में बढ़ी, जब कोरोना काल में कई अन्य पेशों में नौकरियां छिनने के बाद बड़ी संख्या में लोग सब्जी के कारोबार में उतरे थे।

इनका कहना

बाजारों में पार्किंग और चूने की लाइनिंग के नियम का पालन करवाने प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए राजस्व अमले को हिदायत दी जाएगी। बाजार शिफ्टिंग के पुराने प्रोजेक्टों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी।

- ओमपाल सिंह भदौरिया,
सीएमओ नपा बैतूल

साप्ताहिक बाजार में जिन जगहों पर परेशानी हो रही है। वहां पर ट्रैफिक अमले को विशेष निर्देश दिए जाएंगे। शहर के सभी साप्ताहिक बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाएंगे।

-गजेन्द्र केन,
यातायात प्रभारी, बैतूल

महावीर जयंती पर स्कूल के विद्यार्थी दौड़ लगाकर देंगे अहिंसा का संदेश

सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल कर रहा रन फॉर अहिंसा का आयोजन

बैतूल। सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल ने भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती पर 21 अप्रैल को सुबह 6 बजे 'रन फॉर अहिंसा' का आयोजन किया है। इस रन में स्कूल के छात्र दौड़ कर अहिंसा का संदेश देंगे। रन फॉर अहिंसा श्री जैन दादावारी से शुरू होकर शहर के मुख्य चौकों तक पहुंचेगी। स्कूल परिवार ने आम जनता से भागीदारी की अपील की है, जिससे स्वस्थ्य और संवेदनशील समाज की रचना हो सके। यह रन न केवल अच्छे स्वास्थ्य के प्रयास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि अहिंसा और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है अहिंसा के महत्व को समझाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। रन में शामिल होने वाले छात्र अपने प्रेम और समर्थन के साथ एक साथ दौड़ेंगे, जो समाज में अहिंसा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। रन पर अहिंसा शहर के मुख्य मार्गो से निकलेगी जिससे समाज के हर वर्ग को सामूहिकता के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। स्कूल का तर्क है कि इस आयोजन में समाज की साझेदारी से बच्चों को सही दिशा में गाइड किया जा सकेगा, ताकि वे समय के साथ समाज के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में भी सक्रिय भागीदार बन सकें।

शहर के इन मार्गो से निकलेगी रन फॉर अहिंसा मैराथन- स्कूल प्रबंधन ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्मः के शब्द अहिंसा का अर्थ है। हिंसा का अभाव, या अन्य जीवों को नुकसान पहुँचाने की इच्छा का अभाव से प्रेरणा लेकर यह दौड़ श्री जैन दादावारी से शरू होकर थाना रोड होते हुए लक्ष्मी चौक, नेहरु पार्क चौक, कारगिल चौक, गुरुद्वारा रोड, मैकेनिक चौक, दिलबहार चौक, गुजरती जैन मंदिर से पुराना रोजगार दफ्तर पर समाप्त होगी। आयोजन का उद्देश्य छात्र एवं छात्रों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और समाज को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। स्कूल परिवार ने सभी बैतूल की जनता से अपील की है कि इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।

स्थगन आदेश के बावजूद नाले पर बेधड़क किया जा रहा मकान निर्माण

वार्डवासियों की शिकायत के बाद भी नहीं हो रही ठोस कार्यवाही

बैतूल। नगर पालिका बैतूल से स्थगन के बावजूद अर्जुन नगर के सरकारी नाले पर मकान निर्माण कार्य बेधड़क किया जा रहा है। बता दें कि इस निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए अर्जुन नगर के समस्त रहवासी की शिकायत के बाद अपर कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारी को पत्र प्रेषित कर निर्माण कार्य को रोकने के संबंध में आदेश जारी किए थे।

वार्ड वासी शिवदयाल ठाकुर, दिनेश नरवरे, सुनीता सोलंकी, मोहन शर्मा आकाश आदि ने बताया कि अर्जुन वार्ड निवासी कांती नरवरे पति किशोरी लाल नरवरे, द्वारा अर्जुन वार्ड में स्थित खसरा कमांक 152/144 पर भवन निर्माण किया जा रहा है। नाले पर कॉलम खोदे जाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। नपा ने निकाय द्वारा जारी भवन अनुज्ञा को शिकायत की पूर्ण जॉच एवं अंतिम आदेश होने तक किये जा रहे भवन निर्माण को तत्काल रोके जाने के संबंध में इस तरह आदेश जारी किए थे, आदेश की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्यवाही की भी चेतावनी दी थी। इसके बावजूद अनावेदक द्वारा प्रशासन के आदेशों की अवहेलना भवन निर्माण किया जा रहा है।

प्रचार-प्रसार हेतु संबद्ध वाहन की अनुमति 5 मई तक

बैतूल। निर्वाचन आयोग द्वारा हेमंत वागद्रे द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए वाहन स्कॉर्पियो एमपी-04-बीसी 7750 एवं इनोवा एमपी 04 जेडजे 5536 को पूर्व में दी गई अनुमति में संशोधन किया गया है।

मतदान तिथि में संशोधन हो जाने के कारण अब ये वाहन 5 मई 2024 की शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार कर सकेंगे। अपर कलेक्टर बैतूल जयप्रकाश सैय्याम द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है।

एक अन्य आदेश के अनुसार बसंत माकोड़े द्वारा भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उईके के पक्ष में वाहन पिकअप वेन अशोक लिलेंड एमपी 48-जी-1918 को प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। वाहन 5 मई 2024 की शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में 26 अप्रैल की मतदान तिथि 7 मई हो जाने के कारण 24 अप्रैल तक दी गई अनुमति को 5 मई 2024 तक के लिए संशोधित किया गया है।

इंटेकवेल से जुड़ा हरदौली पंप हाउस

10 वार्डों की पेयजल वितरण प्रणाली हुई प्रभावित

वाटर सप्लाई हुई प्रारंभ, अब होगा सुधार

बैतूल/ मुलताई। हरदौली जल आवर्धन योजना पंप हाउस को हरदौली बांध में बने इंटेकवेल से जोड़ने की प्रक्रिया आज पूर्ण हो गई और इसके साथ ही दो दिनों से बंद हरदौली से मुलताई पानी की सप्लाई प्रारंभ कर दी गई है। हरदोली पंप को इटेकवेल से जोड़ने के कार्य के चलते दो दिनों से हरदौली का पानी मुलताई ही नहीं पहुंच रहा था जिससे नगर के 10 वार्डों की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई थी। और उसके साथ ही हरदौली जल आवर्धन योजना के पेयजल घटक के ठेकेदार आदि एक्वा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक चरण और पूरा कर लिया है किंतु क्या इंटेकवेल से पंप हाउस समवेल जोड़े जाने के बाद इसका फायदा नगर की पेयजल आपूर्ति को हो सकेगा इसको लेकर अभी संचय की स्थिति बनी हुई है।

इंटेकवेल पर प्रारंभ हुआ पानी का मीटर- इंटेकवेल पंप हाउस से जुड़ने के साथ ही हरदौली बांध पर पानी का मीटर भी प्रारंभ हो गया है और आज के बाद यह पता चल सकेगा कि प्रतिदिन बांध इंटेकवेल से कितना पानी फिल्टर प्लांट में भेजा जा रहा है। इंटेकवेल फिल्टर प्लांट पंप से जुड़ने के पहले 20-20 एचपी की दो मोटर से 40 एचपी पानी फिल्टर प्लांट पहुंच रहा था जहां अनुमानित 15 लाख लीटर पानी पंप हाउस पहुंचने में 22 घंटे लग रहे थे। अब आदि एक्वा कंपनी ने 75-75 एचपी की दो मोटर एक के बाद एक काम करेगी एक दिन में और एक रात में जिससे जहां बिजली का बिल कम होगा वही 22 घंटे का कार्य 8 घंटे में पूर्ण हो सकेगा।

समय और बिजली की होगी बचत किंतु नगर में जल आवक रहेगी यथावत- मुलताई नगर का दुर्भाग्य कहे या राजनीति यहां हर योजना को पलीता लगते देखना आम सा हो गया है। जहां संपूर्ण देश में योजना का आरंभ सीधी तरफ से होता है हमारे यहां उल्टे तरफ से होता है । बांध के बाद सबसे पहले जिस इंटेकवेल का निर्माण होना था फिल्टर प्लांट पंप हाउस चालू होने के 1 वर्ष बाद आज इंटेकवेल को पंप हाउस से जोड़ा गया है अब तक सीधे बांध से पानी फिल्टर प्लांट में आ रहा था। किंतु उसके बावजूद भी इंटेकवेल से मुलताई जो पानी भेजा जा रहा है उसमें वृद्धि नहीं हो सकेगी उसका कारण यह है कि हमारे पास सिर्फ एक समवेल है मुलताई की पेयजल वितरण प्रणाली में सुधार के लिए नगर की पाइपलाइन व्यवस्था में सुधार करना होगा इसके प्रयास अब भी होते दिखाई नहीं दे रहे हैं।

इनका कहना

हरदौली बांध पर हो रहे सुधार कार्य के चलते दो दिनों से लगभग 10 वार्ड की पेयजल वितरण प्रणाली प्रभावित हुई है अब फिल्टर प्लांट से मुलताई पानी आना प्रारंभ हो गया है शीघ्र ही पेयजल वितरण प्रणाली मे सुधार हो सकेगा।

-योगेश अनेराव,
उपयंत्री नगर पालिका मुलताई

13वें वर्ष में स्वर्ण रथ पर नगर भ्रमण पर निकलेंगे श्री मेंहदीपुर बालाजी

चांदी के चरण किए जाएंगे समर्पित, समिति की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी

बैतूल। श्री मेंहदीपुर बालाजी भक्त मंडल समिति बैतूल द्वारा इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर 23 अप्रैल दिन मंगलवार को सायं 5 बजे कोठी बाजार स्थित श्री हनुमान मंदिर न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड के सामने से श्री मेंहदीपुर बालाजी महाराज की विशाल रथयात्रा निकाली जाएगी। श्री घाटा मेंहदीपुर बालाजी महाराज द्वारा रथ पर बैठकर नगर भ्रमण किया जाएगा। समिति का लगातार 13वें वर्ष पर पदार्पण होने पर इस वर्ष भी समिति द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। रथ पर कलाकारी एवं रंग-रोगन का कार्य बैतूल के कलाकार दिग्विजय बरदे तथा श्याम सोनी द्वारा अपने साथियों के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। भक्तों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते

हुए बालाजी के रथ के रस्सों की लंबाई भी बढ़ाई जा रही है। रथ को महिला एवं पुरूष अलग-अलग रस्सों से खीचेंगे। यात्रा प्रतिवर्षानुसार श्री हनुमान मंदिर न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड से शाम 5 बजे निकलकर थाना रोड, लक्ष्मी चौक, मुल्लाजी पेट्रोल पंप से होते हुए टांगा स्टैंड गंज, बिजासनी माता मंदिर से होते हुए गंज माता मंदिर पेट्रोल पंप के पास समाप्त होगी।

चांदी की चरण पादुका की जाएगी समर्पित- श्री मेंहदीपुर बालाजी भक्त मंडल समिति के सदस्यों द्वारा श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में चांदी की चरण पादुका की समर्पित की जाएगी। समिति द्वारा कलकत्ता पश्चिम बंगाल के कारीगरों से करीब 1 किलो वजनी चांदी के चरणों का निर्माण करवाया गया हैं। समिति द्वारा पिछले वर्ष भी 3 चांदी के छत्र श्री मेंहदीपुर बालाजी के रथ में भेंट किये गये थे।

बालाजी को श्रद्धालु लगायेंगे अर्जिया- श्री मेंहदीपुर बालाजी का मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित हैं, जहां पर हनुमान जी बालरूप में विराजित हैं। जिनके साथ श्री प्रेतराज सरकार तथा भैरव बाबा विराजमान है। मंदिर में वर्षो से मान्यता हैं कि जो भी भक्त मंदिर में अपनी अर्जी एक छोटे से कोरे लाल कपड़े में दस रूपये के सिक्के 11 चावल के दाने के साथ एक कागज पर अपनी मनोकामना लिखकर चढ़ाते है उसे बालाजी महाराज अवश्य स्वीकार करते हैं। बैतूल में निकल रही बालाजी के रथ में भक्त अपनी अर्जी लगा सकते है, जिसे समिति के सदस्यों द्वारा दौसा राजस्थान स्थित श्री मेंहदीपुर बालाजी मंदिर में अर्पित की जाएगी। समिति के सदस्यों द्वारा हर वर्ष रथयात्रा के पश्चात् भक्तों द्वारा चढ़ाई गई अर्जियां, नगद भेंट आदि को श्री मेंहदीपुर बालाजी के मंदिर में जाकर भेंट किया जाता हैं।

पांच जगह होगी महाआरती- श्री घाटा मेंहदीपुर बालाजी की महाआरती का आयोजन पांच स्थानों पर किया जा रहा है। पहली महाआरती श्री हनुमान मंदिर न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड के सामने, दूसरी महाआरती दीक्षित निवास थाना रोड, तीसरी महाआरती लक्ष्मी चौक, चौथी महाआरती बिजासनी माता मंदिर, तथा पांचवी महाआरती यात्रा समाप्त होने पर माता मंदिर गंज पेट्रोल पंप पर की जाएगी। समिति ने नगर की सेवाभावी जनता से अपील की है कि सभी भक्त अपने-अपने घर के सामने रंगोली डालकर और पांच दीपक जलाकर भगवान बालाजी का अभिनंदन करें। वहीं आरती के बाद बालाजी महाराज के पवित्र छीटें प्रसाद स्वरूप दिये जाएंगे। समिति द्वारा रथयात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं, सभी तैयारियां अंतिम चरणों में हैं।

रामू को वोट देकर जनता एक सशक्त और सक्रिय सांसद चुनेगी: डागा

कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक ने विभिन्न ग्रामों में आयोजित की चुनावी बैठकें

बैतूल। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम और पूर्व विधायक निलय डागा ने शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बारव्ही, ढोडरामोहार, सेलगांव, चारबन, रेड़वा, थावड़ी, गोंडीगौला, बयावाड़ी, बघोली में चुनावी बैठकें आयोजित की। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वागद्रे, उपाध्यक्ष लवलेश बब्बा राठौर भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इन बैठकों में उन्होंने नए रणनीतिक उत्तरदायित्वों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों के बीच साझा किया और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। यह चुनावी बैठकें चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो विभाजित वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठकों में लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम और पूर्व विधायक निलय डागा ने स्थानीय जनता के मुद्दों पर गहराई से विचार किया। इन बैठकों में उन्होंने चुनावी रणनीति और चुनाव प्रचार की योजना तय की।

इन बैठकों में नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों

को सुनकर, रामू टेकाम और निलय डागा ने अपने चुनावी एजेंडे को और भी मजबूत और व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। बैठकों में, रामू टेकाम और निलय डागा ने गांव के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कांग्रेस सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर विचार किया और संभावित समाधान पर ध्यान दिया। बैठक में पूर्व विधायक ने जनता को उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कांग्रेस के साथ उनकी उम्मीद का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा की सरकार को लेकर चिंता जताई और उनके निर्णयों पर सवाल उठाया। बैठक में पूर्व विधायक ने देश में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को उठाया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा की सरकार की नीतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने विकास और समृद्धि के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया और जनता के साथ मिलकर एक सशक्त और समृद्ध भारत की दिशा में काम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि जनता रामू को अपना विश्वास देकर एक सशक्त और सक्रिय सांसद चुनेगी। वहीं लोकसभा प्रत्याशी रामू ने अपने उम्मीदवारी को जनता के हित में समर्पित किया और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के मामलों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया और उनके साथ मिलकर विकास और प्रगति की दिशा में काम करने का वादा किया।

उम्मीदवार को लेकर भाजपाईयों में अंर्तकलह कार्यकर्ताओं के स्थान पर कांग्रेसियों को तहज़ीब..

नर्मदापुरम- संजीव डे राय। मतदान की नजदीक आ रही तारीख को लेकर प्रशासन की अलर्टनेस तेज हो गई। 18 वी लोकतंत्री य चुनावी उत्सव की तैयारी को लेकर प्रशासन कितना सजग और उत्साहित हैं उतनी उमंग और उत्साह यहां राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में नजर नहीं आ रहा। भाजपा का गढ़ कहे जाते होशंगाबाद जिले की चारों सीटों पर हालांकि भाजपा का कब्जा है पर चुनाव जीतते इन प्रत्याशियों के विजय वोटों की संख्या का ग्राफ नीचे जा चुका, 18 वी लोकसभा चुनाव का जो उत्साह उम्मीदवार की घोषणा के पहले भाजपाई कार्यकर्ताओं में हुआ करता था वह धीरे-धीरे मद्धिम हो गया। होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पसंद दर्शन सिंह चौधरी एक थोपा गया निर्णय सामने आया, एक तरह से विधायकों को यह पसंद नहीं..? पार्टी ने लिए भाजपाई कार्यकर्ता क्या ठंडी, गर्मी और क्या बरसात सभी मौसम में जी जान लगा देते थे वे आज सुस्त और चापलूसी कर रहे जिलाध्यक्ष और विधायक तो कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करते वे उन कांग्रेसियों को ज्यादा महत्व दे रहे जो भाजपा में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव की कमान बतौर प्रभारी वे संभाल रहे। प्रधानमंत्री की पिपरिया में आयोजित सभा मे फिर जनरल नेताओं की जमकर उपेक्षा दिखाई दी पिपरिया विधायक को दरकिनार किया गया। यहां जिलाध्यक्ष ने राव उदयप्रताप और राव उदय प्रताप के सारे व्यवसायिक मित्रों को पदों से नवाज रखा है आयोजन में एक तरफा उनकी वजनदारी रही.. कांग्रेस से पार्टी में आई नेत्रियों को मंच पर मौका दिया, भाजपा के पूर्व विधायक तीन बार के जिलाध्यक्ष हरि जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्पत मूंदड़ा तक भीड़ में धक्के खाते नजर आए चार जिले दो लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 महामंत्री है पर कार्यक्रम के मंच पर एक महामंत्री प्रीति शुक्ला को जगह और भाषण देने का मौका दिया गया संसदीय क्षेत्र में 39 मंडल अध्यक्ष हैं जिनमें राहुल सोलंकी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष की ज्यादा वजनदारी, आखिर इतनी उथल-पुथल का राज क्या..? इधर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का पूरी तरह टोटा दिखाई दिया लेकिन क्षेत्रीय तासीर सनाढ्य या धनाढ्य वाला उम्मीदवार ब्राह्मणों को एक सूत्र में पिरोने सहायक साबित हो रहा। भाजपा से कांग्रेस में आए गिरजा शंकर शर्मा के घर से चलाई जा रही कांग्रेस इस समय कमजोर दिखाई जरुर देती लेकिन एक ही घर से चलने वाली कांग्रेस और भाजपा का गुणा-भाग भाजपा के लिए मुसीबत साबित न हो .. इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस परिवार के सामने राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया को हाथ बांधकर पीछे खड़े रहना पड़ा उस शख्स के पीछे अब हाथ बांधकर परिवार को खड़ा रहना वरदास्त नहीं.. ऊपर से फिर दर्शन सिंह चौधरी को थोपना कोई भी राजनीतिक नई दुकान खुले पसंद नहीं करेगा।

पुलिस ने की अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

बैतूल। लोकसभा आम चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, इस तारतम्य में संपूर्ण जिले में विशेष अभियान चलाकर चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जा रहा है, चुनाव को प्रभावित करने में अवैध शराब का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है इसी कारण से अवैध शराब पर पुलिस की विशेष नजर होती है, दिनांक 17/04/24 को मोहदा थाना प्रभारी नेपाल सिंह ठाकुर को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि विनय आर्य निवासी हिडली भीमपुर के द्वारा मारुति 800 कार क्रमांक MP04HC2065 में अवैध शराब लेकर ग्राम पिपरिया तरफ से आ रहा है थाना प्रभारी मोहदा द्वारा तत्काल सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया व पुलिस टीम लेकर तुरंत मुस्तैदी से संगवानी जोड़ पर पहुंच कर सूचना की तस्दीक हेतु घात लगाकर उक्त वाहन के आने की प्रतीक्षा करने लगे जैसे ही उक्त हुलिए का वाहन आते दिखा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका पुलिस टीम को देखकर उक्त वाहन चालक विनय आर्य गाड़ी रोक कर रात अंधेरे का लाभ लेकर भाग गया पुलिस द्वारा साक्षियो के समक्ष वाहन मारुति 800 कार क्रमांक MP04HC2065 को चेक किया जिसमे खाकी रंग की 14 पेटियों में ऑफिसर चॉइस कंपनी की व्हिस्की के प्रत्येक पेटी में 48 क्वार्टर 180 एमएल की कुल 672 क्वार्टर में 120 लीटर 960 मिलीलीटर कुल कीमती 100800 रुपए की एवं वाहन मारुति 800 कार क्रमांक MP04HC2065 कीमती 90000 को पुलिस द्वारा साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्त किया गया बाद वाहन मय अवैध शराब के थाने लाकर मालखाना जमा किया गया।

भाजपा के शासन में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, मुख्यमंत्री ने जनता-जनार्दन से दो हाथ उठकर संकल्प दिलाया भाजपा को विजयी बनाएं

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। भाजपा के शासन में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास मूल्य मंत्र है। उक्त उद्गार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सोहागपुर के रानी लक्ष्मीबाई मंच पर नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी दर्शनसिंह चौधरी के समर्थन में आयोजित आमसभा के अवसर पर कहें। आपने अपने अधिकांश उद्बोधन में कांग्रेस एवं पाकिस्तान, आतंकी हमलों आदि पर विस्तृत वर्णन किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा भाजपा ने अपना संकल्प पूरा करके अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया है।अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी रास्ता देख रही है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में उपस्थित जन समुदाय को दोनों हाथ उठाकर भाजपा को वोट करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, भाजपा प्रत्याशी दर्शनसिंह चौधरी के अलावा राज्य सभा सदस्य, विधायक गण , भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता तथा जनसमुदाय उपस्थित था। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा सोहागपुर विधानसभा मीडिया प्रभारी राजेश शुक्ला एवं संजीव शुक्ला ने किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को अयोध्या श्री राम मंदिर की आकृति भेंट की गई।

व्यय प्रेक्षक मोहम्मद शमशाद आलम ने देखी मीडिया मॉनिटरिंग की कार्यवाही

ज़िला व्यय अनुवीक्षण सेल सहित एसएसटी, वीएसटी कंट्रोल रूम का भी किया निरीक्षण

धार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक निर्वाचन 2024 के मद्देनजर नियुक्त व्यय प्रेक्षक मोहम्मद शमशाद आलम आज जिला पंचायत सभागार में लोकसभा निर्वाचन के तहत स्थापित किए गए कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का अवलोकन कर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों और सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकरियां प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार रावत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचन संबंधी शिकायतों का त्वरित और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण में सी-विजिल एप बेहद मददगार हो रहा है। जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बाद से सी-विजिल एप के माध्यम से अब तक प्राप्त 71 शिकायतों का त्वरित और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया गया। जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित यह कंट्रोल रूम 24ङ्क7 कार्य कर रहा है। साथ ही जिले के नागरीकगण यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है।

निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक मोहम्मद शमशाद आलम ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्टों में सतत् निगरानी रखे जाने, चेकपोस्टों में लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरे सुचारू कार्य करने सहित क्रिटीकल और वल्नरेबल मतदान केन्द्रों पर भी निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात वे तहसील कार्यालय में स्थापित किए गए एसएसटी, वीएसटी कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। यहां उन्होंने निगरानी सहित आने वाली शिकायतों पर तत्काल पहुंचने के संबंध में जानकारी ली। साथ ही एसएसटी, वीएसटी के सदस्यों से भी चर्चा की। इसके बाद वे कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थापित किए गए ज़िला व्यय अनुवीक्षण सेल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों से व्यय के संबंध में जानकारियां लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

व्यय निगरानी के संबंध में विभिन्न एजेंसी के बेहतर समन्वय पर व्यय प्रेक्षक ने जताई संतुष्टि

व्यय अनुवीक्षण में जुटे अधिकारियों की बैठक संपन्न

धार। सही व्यक्ति में सुरक्षा का भाव रहे,ग़लत व्यक्तियों में भय व्याप्त हो। व्यय प्रेक्षक शमशाद आलम ने यह बात आज कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित व्यय अनुवीक्षण में जुटे अधिकारियों की बैठक में कही। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। व्यय निगरानी के संबंध में विभिन्न एजेन्सी के बेहतर समन्वय पर व्यय प्रेक्षक ने संतुष्टि ज़ाहिर की। बैठक में बैंकों से नकद निकासी का अनुवीक्षण, एटीएम वाहन एवं अन्य द्वारा नगदी ले जाने के लिए एसओपी, आयकर विभाग द्वारा अनुवीक्षण, आयकर कर्मियों की तैनाती, नगदी के बारे में एफ एस टी / एस एस टी को प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही,सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम ड्यूटी,जीएसटी,तेल कम्पनियों के लिए एसओपी, ईंधन खपत की निगरानी,मदिरा का भण्डारण एवं अवैध वितरण को रोकने,व्यय अनुवीक्षण में एमसीएमसी कमेटी, पुलिस, वन, खनिज और नारकोटिक विभाग की भूमिका पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।

जिले में हाथ का साथ छोड़ती महिला टीम, क्या कांग्रेस का बड़ा नुकसान करेंगी

आमला। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई किसी पार्टी से नहीं बल्कि शक्ति के साथ है अब राहुल गांधी ने यें बात किस परिप्रेक्ष्य और किस भाव से यें कहा था, यें वही भली बातें जानते हैं,और उनके इस वक्तव्य को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा भी बना दिया था, किंतु राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद जिले में जिस तरह से कांग्रेस महिला विहीन होती जा रही है, उससे कांग्रेस के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव और ज्यादा चुनौती पूर्ण हो सकता है, बीते तमाम लगभग तीन दशकों से लगातार जिस तरह से जिले पर भाजपा का दबदबा रहा है, ऐसे में बीते कुछ दिनों से जिला कांग्रेस में जिस तरह से टूट, भगदड़, अविश्वास और आरोपों की बाढ़ आई हुई है, उसको देखकर लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती का पाट और ज्यादा चौड़ा हो गया है, इस पर सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि जिला कांग्रेस में महिला टीम लगभग ना के बराबर हो गई है, जिससे कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगने लगे हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह सामने आई पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस पर भरोसा किया और फिर अचानक ही उनका कांग्रेस विरोधी हो जाना, एक बड़ा संदेश देता है तो इसके अलावा पिछले दिनों पूर्व कांग्रेस विधायक सुनीता बेलें का भाजपा में जाना, आमला से लेकर बैतूल तक

महिला कांग्रेस की निष्क्रियता और पार्टी के अंदर के विश्वास और डर को परिलक्षित करता है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान हमने जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मोनिका निरापुरे से बात की तो उन्होंने इस बात को तो माना है कि महिला कांग्रेस फिलहाल एक्टिव मोड में नहीं है, इन्होंने बताया कि इस समय त्यौहार वगैरा भी चल रहे हैं किंतु अगले कुछ दिनों में जिले में महिला कांग्रेस फिर से सक्रिय मोड में दिखाई देगी, किंतु इस दौरान श्रीमती निरापुरे ने यह जरूर बताया है कि पार्टी द्वारा फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, श्रीमती निरापुरे ने कांग्रेस की जीत का भरोसा भी जताया हैं।

निशा बांगरे ने कांग्रेस को महिला विरोधी कहा- पूर्व डिप्टी कलेक्टर और कांग्रेस की सदस्यता लेकर बीते वर्ष आमला की सुरक्षित विद्यानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सपना संजो चुकी निशा बांगरे कभी कांग्रेस की तारीफों के क़सीदे गढ़ा करती थी, किन्तु जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से उन्हें तवज्जो नहीं मिली, उससे वो वापस अपनी कलक्टरी पर लौटना चाहती हैं, वो कांग्रेस से अपना इस्तीफा भी दें चुकी हैं, इस मौके पर जब हमने उनसे बात की तों उन्होंने कहा की बाबा साहेब नें कभी कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज कहा था, आज कांग्रेस पूरी तरह डूब चुकी हैं, इन्होने कांग्रेस के जिम्मेदारो पर सवाल उठाते हुए कहा की कांग्रेस मे कोई सिस्टम काम नहीं करता हैं, कांग्रेस यूथ का इस्तेमाल करना भी नहीं जानती हैं,इसके अलावा इन्होने कांग्रेस को महिला विरोधी भी बताया हैं,जिसके चलते कांग्रेस की दुर्दशा हो रहीं हैं, एक सवाल के जवाब मे श्रीमती बांगरे नें कहा की अभी ना कभी वो कांग्रेस की कोई मदद नहीं करेंगी, इन्होने बताया की अभी उनके सामने पूरा आसमान खुला हैं, वो किसी भी मंच से जरूरतमन्द की सेवा करती रहेंगी।

आज आमला मे कमलनाथ की सभा- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की शनिवार को आमला के चुटकी मे एक चुनावी सभा होने जा रहीं हैं, इसके लिए कांग्रेस द्वारा कई तैयारी की गई हैं।

महावीर जयंती धूम-धाम से मनाई जावेगी 21 अप्रैल को

● आकर्षक भव्य शोभायात्रा में सम्मिलित होंगे चांदी के रथ ● मतदान जागरूकता रैली रहेगी आकर्षण का केन्द्र ● 20 अप्रैल को होगा रंगारंग सांस्कृति कार्यक्रम ● पूर्व संध्या 20 अप्रेल को निकलेगी विशाल वाहन रैली ● कुष्ठधाम, अंधशाला एवं वृद्धाश्रम पर होगा भोजन वितरण

देवास। जियो और जिने दो का अमर संदेश देकर अहिंसा का पाठ सम्पूर्ण विश्व को पढ़ाने वाले जैन जगत के 24 वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामीजी का जन्म कल्याणक दिवस महावीर जंयती समग्र जैन समाज देवास द्वारा 21 अप्रैल रविवार को अपूर्व हर्षोल्लास एवं भक्ति भावना के साथ भव्यतम रूप से मनाई जावेगी। इस अवसर पर विशाल आकर्षक शोभा यात्रा प्रात 8.30 बजे श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तुकोगंज रोड से निकाली जाएगी। उल्लेखनीय है विगत 53 वर्षो से दिगम्बर एवं श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा सामूहिक रूप से महावीर जयंती मनाई जा रही है। 20 अप्रेल जयंति पूर्व संध्या पर विशाल वाहन रैली शाम 5 बजे सयाजी द्वार से निकाली जाएगी। शाम 7 बजे एक शाम महावीर के नाम के अंतर्गत समाज की माता बहनों एवं बालिकाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति मंडी धर्मशाला पर दी जाएगी। 21 अप्रेल को प्रात 7.30 से 8.30 बजे तक श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तुकोगंज रोड़ पर समग्र जैन समाज की नवकारशी आयोजित होगी।

ये भव्य आकर्षण होंगे शोभा-यात्रा के- अनेक आकर्षणों से सुसज्जित विशाल जन समुदाय को समेटे इस शोभा-यात्रा में चांदी के रथ में भगवान महावीर स्वामी विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सुसज्जित झांकियाँ भी चल समारोह की शोभा बढ़ायेगी। भजन मंडलियां भक्ति गीत गाते हुए चलेगी। शोभा यात्रा में जैन समाज द्वारा मतदान हेतु जागरूकता लाने के लिए मातृ शक्ति अपने दो पहिया वाहनों पर मतदान अपील की तख्तियों के साथ मतदान जागरूकता रैली के रूप में आगे चलेगी। मार्ग में अनेक संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत किया जायेगा। महिलायें मस्तक पर 108 कलश धारण किये हुए शोभायात्रा में उपस्थित रहेगी। देवास नगर के सभी जैन मंदिर एवं स्थानक पर दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए बड़ा बाजार, रज्जब अली मार्ग, कवि कालिदास मार्ग, जनता बैंक, कैलाश जैन मानव चौराहा, एम.जी. रोड़, पिपली बाजार, सरदार पटेल मार्ग, सुतार बाखल, पीठा रोड़, जवाहर चौक होते हुए श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर तुकोगंज रोड़ एवं श्रमण संस्कृति सदन नयापुरा पर शोभा यात्रा समाप्त होगी। यहां पर श्रीजी का अभिषेक संपन्न होगा। तत्पश्चात् प्रात 11.30 बजे से श्वेताम्बर जैन समाज देवास का स्वामी-वात्सल्य का आयोजन मण्डी धर्मशाला पर होगा। नेत्रहीन बालक/बालिकाओं को तथा वृद्धाश्रम एवं हामूखेड़ी कुष्ठ धाम पर निराश्रितों को भोजन करवाकर अन्नदान किया जावेगा। रात्रि को सभी जैन मंदिरों में भक्ति भावना के विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। देवास नगर के सभी जिनालयों पर विशेष विद्युत सज्जा एवं सजावट की जायेगी।

महावीर जयंती उत्सव समिति के अध्यक्ष विजय जैन एवं पदाधिकारी शैलेन्द्र चौधरी, मनीष जैन,अतुल जैन, संजय कटारिया, नितिन जैन, पारस जैन, विकास जैन, मुकेश चौधरी, विशाल जैन, रिंकेश जैन, निलेश जैन, पंकज चौधरी एवं पारस जैन ने कार्यक्रम सफल बनाने की अपील की है।

हमें नकारात्मक ताकतों को परास्त करना है : श्री सोलंकी

अधिवक्ताओं से परिचर्चा करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने व्यक्त किये विचार

देवास। अधिवक्ता क्रांति के अग्रदुत माने जाते है। जनता आप पर भरोसा करती है। आपकी राय पर चलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका अनिवार्य है। केन्द्रीय चुनाव कार्यालय पर अधिवक्तागणों से परिचर्चा करते हुए उक्त विचार देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेन्द्र सिंह सोलंकी ने व्यक्त किये। श्री सोलंकी ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में चारो तरफ विकास हो रहा है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। ऐसे समय में नकारात्मक ताकतें देश को कमजोर करने में जूटी हुई है। हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए ये ताकतें देश को तोडने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से विभाजनकारी धारा 370 हटाई, तब भी इन ताकतों ने विरोध किया। तीन तलाक कानून को रद्द करने का विरोध किया। यही नहीं जब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का दिव्य एवं भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। तब भी इन नकारात्मक ताकतों ने विरोध करते हुए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का न्यौता ठुकराया। लोकसभा के इस चुनाव में हमें ऐसी नकारात्मक ताकतों को परास्त करना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के

संकल्प को साकार किया जा सके। हमें अपने परिचितों, पास पड़ोस वालों, पक्षकारों से चर्चा करते हुए मतदान के लिये प्रेरित करना है। परिचर्चा में वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप जाधव, पूर्व देविप्रा अध्यक्ष राजेश यादव, जिला महामंत्री पंकज वर्मा, विधि प्रकोष्ठ के संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश नारायण उपाध्याय, शंकर गिरी गोस्वामी, अभिभाषक संघ देवास के सचिव अतुल पंड्या, उपाध्यक्ष गीता शर्मा, कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह तोमर, सहसचिव जितेंद्र ठाकुर, विधि प्रकोष्ठ जिला सयोंजक हेमन्त शर्मा, अधिवक्ता परिषद के आनंद अधिकारी, सुरेश चौधरी, राजेन्द्र बापना, गजेंद्र वशिष्ठ, रघुवीर यार्डी, प्रकाश सिंह, सोनकच्छ अभिभाषक संघ से जीवन सिंह गुर्जर, कविता सोनी, हाटपीपल्या से कमलेश शर्मा, जितेंद्र सेंधव, राजेन्द्र नागर, त्रिलोक पाटीदार, मिथलेश सोनी, रजनी पांचाल, श्रेया चौबे, साधना काले देवेंद्र सिंह व्यास, हर्षित गावशिन्दे सहित सेकड़ो अधिवक्ता उपस्थित थे। संचालन विधि प्रकोष्ठ के उज्जैन संभाग प्रभारी मनीष पारीक ने किया ।

सीएए कानून का किया विरोध- भाजपा प्रत्याशी श्री सोलंकी ने टुकड़े टुकड़े गैंग एवं विभाजनकारी राजनीतिक पार्टियों पर कड़ा प्रहार करते हुए परिचर्चा में कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार द्वारा पाकिस्तान, बंगलादेश एवं अफगानिस्तान के आए हिन्दू, सिख, बोद्ध एवं पारसी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिये सीएए कानून लागू किया गया।

विश्वकर्मा बढ़ई समाज ने धूमधाम से कराया नवयुगल का विवाह

विधायक एवं रेडक्रॉस सोसायटी अध्यक्ष ने वर वधु को दिया आशीर्वाद

बैतूल। विश्वकर्मा समाज ने शुक्रवार 19 अप्रैल को विश्वकर्मा मंदिर में निशुल्क विवाह महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें नवयुगल का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने नवयुगल को शुभकामनाएं दीं। समाज के इस निशुल्क विवाह महोत्सव ने नवयुगल के जीवन को नई ऊर्जा और खुशियों से भर दिया।

समिति द्वारा किए गए इस कार्यक्रम में समाज के सदस्यों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई, जिससे इस कार्यक्रम को सफलता मिली। यहां पर समाज के सहयोग से नव दंपत्ति को घर गृहस्थी की समस्त सामग्री भी दी गई। विवाह समारोह में सैकड़ों की संख्या में समाज जन उपस्थित थे। आमला, सारनी विधायक डॉ.योगेश पण्डागरे, एवं रेडक्रॉस सोसायटी बैतूल के अध्यक्ष डॉ.अरूण जयसिंगपुरे ने वर वधू को अपने हाथों से भोजन करवाया एवं आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि एक समाज की समृद्धि उसकी एकता और सहयोग से होती है। निशुल्क विवाह का आयोजन करके, विश्वकर्मा बढ़ई समाज ने सहानुभूति और सहयोग का बेहतर उदाहरण पेश किया। यह सामाजिक संदेश हमें उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाता है, जहां हर व्यक्ति का समाज में एक समान महत्व हो। उल्लेखनीय है कि विश्वकर्मा बढ़ई समाज समिति जिला बैतूल के तत्वावधान में सारणी क्षेत्र के सदस्यों की अनुशंसा पर विश्वकर्मा बढ़ई समाज समिति जिला बैतूल द्वारा निःशुल्क विवाह सम्पूर्ण विधि विधान से सम्पन्न करवाया।

विदिशा-रायसेन मेरा बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है : शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में जनसभा को संबोधित किया फिर नामांकन पत्र दाखिल किया

शिवराज ने कहा....
- हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पत्र के हर वचन को पूरा करेंगे
- राहुल गांधी को न हिंदी की समझ और न अंग्रेजी की, हम इटली में नहीं समझा सकते

रायसेन। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है, जो वैचारिक और संस्कारित विचारों की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं जनता का सेवक हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे विदिशा-रायसेन की जनता की सेवा करने का मौका दिया। विदिशा-रायसेन मेरा बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। जब हमारे संघर्ष के दिन थे तब जनता की सेवा के लिए संघर्ष किया और इमरजेंसी में जेल भी गये। आज भी बेटियों को पोते की चाहत में गला घोंटकर मारा जा रहा है। मेरे मन में बेटियों के लिए बहुत सम्मान है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो लाड़ली लक्ष्मी से लाड़ली बहना योजना लेकर आया, ताकि बहन-बेटियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। किसानों और विद्यार्थियों के लिए कई योजनाओं के माध्यम से उनका उत्थान करने का प्रयास किया। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। श्री चौहान ने कहा कि जनता की सेवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार निरंतर विकास की राह पर है और 2024 तक भारत विश्व गुरू बनेगा। दुनिया में भारत का डंका बज रहा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के देश प्रणाम कर रहे हैं।

विदिशा-रायसेन के विकास का रोडमैप तैयार

श्री चौहान ने कहा कि मैं सांसद बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। विदिशा-रायसेन के विकास के विजन और रौडमैप तैयार करके चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि आपकी सेवा कर सकूं। यहां हर क्षेत्र में पहले भी विकास किया गया है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यहां विकास नहीं किया। अब विदिशा-रायसेन में पहली भी हमारी सरकार ने काफी विकास किया और उसका क्रम जारी रहेगा और हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। श्री चौहान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस सीट पर 90 प्रतिशत मतदान कराने की जिम्मेदारी अब आप पर है ,ताकि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतकर यह सीट प्रधानमंत्री को झोली में डालकर उन्हें फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जा सके।

राहुल गांधी को न हिंदी की समझ और न अंग्रेजी की

पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी को ना हिंदी की समझ है और न अंग्रेजी की। संकल्प पत्र में सब कुछ साफ लिखा गया है, लेकिन राहुल गांधी को समझ नहीं आया। हम इटली की भाषा में लिखकर अब राहुल गांधी को नहीं समझा सकते हैं। सोनिया गांधी ने रायबरेली और राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़कर वायनाड को चुना। कांग्रेस ने कभी भी देश के लिए कुछ नहीं किया। डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश में लगातार विकास तेज गति से किया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में मिस्टर बंटाधार के समय ना बिजली मिलती थी न पानी, लेकिन प्रदेश सरकार ने पढ़ाई से लेकर सिंचाई तक की सुविधा किसानों को देकर प्रदेश के हर गांव को लहलहाने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र में दिए गए वचनों की गारंटी को पूरा करेंगे। केंद्र में भी हमारी सरकार रहेगी और प्रदेश में आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार पहले से ही है। जनता से किया गया हर वादा पूरा होगा और प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी।

कांग्रेस ने भगवान श्रीराम का विरोध किया

श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते भगवान राम का भी विरोध किया। रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण तक कांग्रेस ने ठुकरा दिया। 500 सालों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह और रामनवमी पर भगवान राम के सूर्य तिलक पर देश के लोग खुशियां मना रहे थे,लेकिन सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी दुखी थी।

छिंदवाड़ा में वोटिंग के दिन हो गया 'खेला'

बीजेपी में गए मेयर ने मारी पलटी, कहा-कमल नाथ को करें सपोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वोटिंग के दिन छिंदवाड़ा में बड़ा खेला हो गया है। दो अप्रैल को बीजेपी में शामिल होने वाले छिंदवाड़ा मेयर विक्रम अहाके पलट गए हैं। बीजेपी की सदस्यता लेकर वह सांसद नकुल नाथ और कमल नाथ को कोस रहे थे। 17 दिन बाद ही छिंदवाड़ा मेयर का मन बदल गया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि नकुल नाथ को सपोर्ट करें। छिंदवाड़ा मेयर विक्रम अहाके ने कहा कि मैं बिना किसी के दबाव के यह वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया था। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया, मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरे मन में यह ख्याल आ रहा था कि तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो, जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है। विक्रम अहाके ने कहा कि जीवन में राजनीति करने के मौके बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता। आज अगर हम कमलनाथ और नकुल नाथ के साथ खड़े नहीं हुए तो क्योंकि उन्होंने मुझे भी यहां तक पहुंचाया है। उन लोगों ने छिंदवाड़ा का काम किया है। आने वाले समय जो मेरे साथ होगा, वो मुझे पता नहीं है। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि नकुल नाथ को भारी मतों से विजयी बनाएं। विक्रम अहाके को कमल नाथ ने ही छिंदवाड़ा से मेयर का चुनाव लड़वाया था। विक्रम की जीत की तारीफ राहुल गांधी ने भी की थी। 17 दिन पहले वह भोपाल आकर सीएम मोहन यादव के सामने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। अब छिंदवाड़ा मेयर पलट गए हैं, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है।

लीज नवीनीकरण के आवेदन खारिज, विस्थापित परिवारों को नहीं मिल रहा लोन

भोपाल। सिंधी विस्थापित परिवारों को आवंटित वन ट्री हिल्स के भूखंडों की लीज अवधि समाप्त होने से 500 परिवार परेशान हैं। जिला प्रशासन लीज नवीनीकरण नहीं कर रहा है। निजी तौर पर लीज रिन्युवल के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। लीज अवधि समाप्त होने के कारण बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा है। अब यहां के रहवासी लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे आवेदन करने की तैयारी में हैं।

गृह निर्माण समितियों के जरिए हुआ था भूखंड का आवंटन

वन ट्री हिल्स के 500 भूखंड राज्य शासन ने तीन गृह निर्माण समितियों के माध्यम से सिंधी विस्थापित परिवारों को आवंटित किए थे। नवयुवक गृह निर्माण समिति, सिंधु समाज एवं गांधीनगर गृह निर्माण संस्था के माध्यम से लोगों को भूखंड दिए गए थे। शासन ने इनकी लीज अवधि 30 साल तय की थी, साथ ही यह प्रविधान भी किया था कि भूखंडधारी गृह निर्माण संस्थाओं के माध्यम से ही लीज का नवीनीकरण करा सकते हैं। अधिकांश भूखंडों की लीज 2018 में ही समाप्त हो चुकी है। तीनों गृह निर्माण सोसायटियों ने इनका आवंटन एवं निर्धारित लीज शुल्क जमा कर दिया। इसके बाद समितियां भंग कर दी गईं।

नए नियमों का नहीं मिल रहा लाभ

सोसाइटियों के भंग होने के बाद अब लोग निजी आवेदन देकर लीज नवीनीकरण कराना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इन्हें खारिज कर रहा है। पिछले दिनों राज्य शासन ने नियम सरल करते हुए निजी आवेदन पर नवीनीकरण के आदेश जारी किए, लेकिन नए नियम भी इतने जटिल हैं कि अभी तक एक भी परिवार को इसका लाभ नहीं मिला है।

भोपाल सीट पर आखिरी दिन 16 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

28 उम्मीदवारों ने जमा किए 41 फॉर्म, जयश्री ने कांग्रेस से भरा डमी पर्चा

भोपाल। भोपाल लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आखिरी दिन 16 नामांकन जमा किए गए। बैरसिया विधानसभा से कांग्रेस कैंडिडेट रही जयश्री हरिकरण ने भी नामांकन भरा। उन्होंने कांग्रेस की ओर से डमी नामांकन भरा है। 12 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया से लेकर आखिरी दिन 19 अप्रैल तक 28 उम्मीदवारों ने कुल 41 नामांकन भरे हैं। कई कैंडिडेट्स से 3 से 4 नामांकन भरे हैं। शुक्रवार को बहुजन द्रविड़ पार्टी ने दीनदयाल अहिरवाल, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से अजय गोटी, कांग्रेस से जयश्री, मानव समाधान पार्टी से संजय कुमार सरोज, कांग्रेस से अरुण कुमार श्रीवास्तव, निर्दलीय आरके महाजन, प्रेमनारायण स्वर्णकार, हितेंद्र तेजलाल शहारे, मुदित चौरसिया, वीरेंद्र कुमार, अब्दुल ताहिर, मैथिलीकरण गुप्त, राजेश कीर, अजय कुमार पाठ, प्रकाश और एके जिलानी ने नामांकन भरे। शुक्रवार तक कुल 41 कैंडिडेट्स ने नामांकन जमा किए हैं। कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव सबसे अमीर हैं। उनके पास करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं, दूसरे नंबर पर बीजेपी के आलोक शर्मा हैं। उनके पास 8 करोड़ रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति हैं। शर्मा गुरुवार को नामांकन दाखिल कर चुके हैं।

चंदनपुरा में एक कालेज के सामने विचरण कर रहा था बाघ, शहर में मची दहशत

भोपाल। भोज मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले ही तेंदुआ दिखने के चलते पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है लेकिन अब बाघ दिखने के चलते शहरवासियों के बीच और डर समा गया है। गुरुवार को सुबह 6.30 बजे ग्राम चंदनपुरा स्थित जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के गेट के पास बाघ घूमता दिखाई दिया है। वहां कार से घूम रहे नागरिक ने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में बाघ यूनिवर्सिटी के गेट के पास दिखाई देता है फिर वापस जंगल में चला जाता है।

गैर वानिकी गतिविधियों के कारण हो रहे परेशान- राशिद नूर खान ने बताया कि बाघ भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन शहर में बाघ मानव के साथ बिना किसी टकराव के विचरण कर रहा है। कुछ रसूखदारों द्वारा खुलेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ग्राम चंदनपुरा में एमए क्लब चल रहा है। यहां तेज आवाज में डीजे के साथ निजी फार्म पर शादी और पार्टियों का आयोजन होता है। ऐसे आयोजनों से यह जंगल के शिकारी शहर में भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई मैरिज गार्डन भी संचालित हो रहे हैं। जिसकी शिकायत कई बार एनजीटी को की गई है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुरुवार को भी यहां शादी हुई है, जिसके बाद यहां बाघ दिखाई दिया है।

भोपाल प्रदेश की पहली राजधानी है, जिसमें नगर निगम सीमा से सटे क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा बाघों का भ्रमण पाया जाता है। कलियासोत डेम से लेकर केरवा डेम के बीच राजस्व वन क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, वन क्षेत्र एवं किसानों का निजी क्षेत्र है। यह क्षेत्र पहाड़ी है। यहां वन्यप्राणियों के प्राकृतिक रहवास भी है। इस क्षेत्र में कलियासोत एवं केरवा डेम के रूप में जल स्त्रोत भी विद्यमान है। क्षेत्र में लेंटाना का कवर एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्ष भी प्रचुर मात्रा में है। लगभग 357.813 हेक्टेयर राजस्व वन क्षेत्र वर्ष 2003 में राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को हाईटेक वृक्षारोपण के लिए स्थानांतरित किया गया था।

लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, शादी के जोड़े में वोट डालने पहुंचे दूल्हा-दुल्हन

नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। इसी बीच कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है। जो लोकतंत्र के प्रति सजगता बयां कर रही है। ऐसी ही तस्वीर गोटेगांव से सामने आई है जहां मंडला संसदीय क्षेत्र से पहले चरण के मतदान के दौरान एक दूल्हे ने शादी कार्यक्रम को बीच में छोड़कर अपनी पत्नी पूजा मेहरा को मतदान केंद्र ले जाकर मतदान कराया।

दूल्हे योगेश ने बताया कि पूजा की इच्छा के चलते उन्होंने वोटिंग करवाई है। हालांकि उनकी भी यही इच्छा थी कि वह अपनी जीवनसंगिनी के दायित्व को पूरा करने में सहभागी बनें।

बालाघाट: विदाई से पहले डाला वोट- बालाघाट में भी विदाई के पहले दुल्हन ने जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान केंद्र 181 पर पति के साथ पहुंचकर वोट डाला।

डिंडौरी: शादी से पहले किया मतदान- शहर के कस्तूरबा कन्या स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र क्रमांक चार में शादी से पहले दुल्हन शुभांगी यादव ने मतदान किया।

छिंदवाड़ा: नवविवाहित जोड़े ने किया मतदान- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जिले के ग्राम तंसरामाल में नवविवाहित जोड़े दिकलेश साहू और कुसुम साहू ने स्कूल के मतदान केंद्र जाकर वोट डाला।

निजी स्कूलों की मनमानी की जांच के बाद 35 स्कूलों को नोटिस

ग्वालियर। किताबें और स्कूल यूनिफार्म में अभिभावकों के साथ ठगी की शिकायतों के बाद कलेक्टर की ओर से गठित जांच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने गुरूवार को 35 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। कारण बताओ नोटिस में स्कूलों में मिली खामियां व अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा गया है। जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उसमें शहर के नामी-गिरामी स्कूल भी शामिल हैं।

जवाब संतोषजनक न होने पर बढ़ सकती हैं मुश्किल- नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने पर स्कूल संचालकों की मुश्किल बढ़ सकती है। किताबें और स्कूल यूनिफार्म में अभिभावकों से ठगी के मामले में प्रमुखता से अभियान चलाया था जिसमें स्कूल व दुकानदारों की कई खामियों को रखा। इसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर स्कूलों की जांच के लिए संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में जिले में 8 टीमें गठित की गई हैं। बुक, स्टेशनरी व यूनीफार्म बेचने वाली दुकानों की जांच के लिये 7 बिन्दु निर्धारित किए हैं। इसी तरह निजी विद्यालयों के लिये भी 6 बिंदु निर्धारित किए गए। जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया। जांच टीमों की जांच में सामने आया कि स्कूलों में कई अव्यवस्थाएं हैं और स्कूल-ड्रेस के मामलों में भी कई स्कूलों की भूमिका संदिग्ध मिली। एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने अपनी टीमों के साथ यह जांच की। वहीं कलेक्टर ने मार्च में धारा 144 के तहत भी आदेश जारी किया था कि निजी स्कूल अभिभावकों को ड्रेस व किताबों को निर्धारित दुकानों से लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे वरना कार्रवाई की जाएगी।

इन स्कूलों को मिले नोटिस- लिटिल एंजेल हाइस्कूल, द रेडिएंट स्कूल, पोददार इंटरनेशनल स्कूल, रामश्री किड्स स्कूल, आदित्य वलर्ड स्कूल, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, आर्यन स्कूल आफ संस्कार, भारतीय विद्या निकेतन, देहली पब्लिक स्कूल, कार्मल कान्वेंट स्कूल, दून पब्लिक स्कूल, एबनेजर पब्लिक स्कूल, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, आइटीएम ग्लोबल सिथौली, प्रगति विद्यापीठ, वीनस पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल, जेंट जान वियानी स्कूल, मार्निंग स्टार स्कूल मुरार, माउंट लिटेरा जी स्कूल रायरू, किडीज कार्नर स्कूल, मानवेंद्र ग्लोबल स्कूल, बालाजी पब्लिक स्कूल डबरा, नारायणा ई-टेक्नो स्कूल, एस किंडर गार्डन स्कूल, सेंट पीटर्स सिमरिया टेकरी डबरा, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल डबरा, सिल्वर बैल्स पब्लिक स्कूल, रामकृष्ण मिशन थाटीपुर, न्यूट्रिक पब्लिक स्कूल, ग्रीनवुड स्कूल आदित्यपुरम, ऋषिकुल विद्या निकेतन शिवपुरी लिंक रोड, सेवन आई वल्ड स्कूल, अशोका इंटरनेशनल स्कूल, राइज इंटरनेशनल स्कूल नैनागिर।